

संस्करण : मुंबई

वर्ष : 10

अंक : 362

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

मंगलवार, 06 जनवरी, 2026

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक



मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति ...

4 1000 साल पुराने हमलों के बाद भी वैभव के ...

7 दिग्गज ऑलराउंडर ने भारत की अगली ...

संक्षिप्त न्यूज

वेनेजुएला के बाद ईरान में घुसने वाला है अमेरिका? भारत ने जारी की क्या एडवाइजरी

नई दिल्ली। देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर भारत ने ईरान के लिए यात्रा संबंधी चेतावनी जारी की है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचें। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और पहचानकर्ताओं को सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए



और समाचारों के साथ-साथ तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी नजर रखनी चाहिए। ईरान में निवास वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा लें।

भारत ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शासन के खिलाफ कार्रवाई की धमकियों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत का कहना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अपने नागरिकों को निकालने के लिए तैयार है। हालांकि तेहरान में किसी भी विदेशी मिशन ने अब तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। हालांकि, भारतीय सरकार विरोध प्रदर्शन बढ़ने और बाहरी हमला होने पर छात्रों सहित अपने नागरिकों को निकालने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है।

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर पर नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप, जेडीएस ने वापस ली शिकायत

मुंबई। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसे लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर पर गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। वहीं जनता दल सेक्युलर ने कोलाबा इलाके में नामांकन प्रक्रिया में कथित तौर पर होने वाली गड़बड़ियों के शिकायत को वापस ले लिया। लेकिन पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ ने कहा कि वह नार्वेकर के खिलाफ अपनी शिकायत को जारी रखेंगे।

राठौड़ ने कहा कि जेडीएस पीछे जरूर हटी है लेकिन हार नहीं मानी है। राज्य चुनाव आयोग के पास उनकी शिकायत अभी भी है, जिसे वह एक तार्किक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। कई विपक्षी पार्टियों ने नार्वेकर पर चुनावों के लिए लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने, नामांकन प्रक्रिया में दखल देने और प्रक्रिया से जुड़े सीसीटीव फुटेज से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।

भाजपा विधायक नार्वेकर ने सभी

आरोपों को खारिज किया



जेडीएस ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए अपने तीन उम्मीदवारों में से दो के नामांकन पेपर स्वीकार होने के बाद अपनी शिकायत वापस ले ली। आगे उन्होंने कहा कि

पार्टी को नामांकन के बारे में जानकारी के बिना ही शिकायत दर्ज करा दी थी।

पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ ने की नीजि शिकायत पर जांच की मांग

कहा जो भी शिकायत दर्ज की जाएगी, संबंधित अधिकारी उसकी जांच करेंगे। क्या है कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन का विवाद यह विवाद कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड 225, 226 और 227 से संबंधित है, जहां नार्वेकर के रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें उनके भाई मकरंद नार्वेकर, बहन गौरी शिवलकर और भाभी हर्षिता शिवलकर शामिल हैं। कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष के रिश्तेदारों का निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नामांकन करने से रोका गया। राठौड़ ने पहले आरोप लगाया था कि जब वह अपने बेटे के नामांकन के लिए उसके साथ गए थे, तो नार्वेकर ने उनके मौजूद रहने का विरोध किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नार्वेकर 30 दिसंबर को शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में रहे और अधिकारियों को नामांकन दस्तावेजों की प्रक्रिया को धीरे करने का निर्देश दिया।

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा:

बिष्णुपुर में दोहरे धमाके, दो घायल; सुरक्षा चूक पर भड़के लोग, किया ये बड़ा एलान

इंफाल। मणिपुर में शांति की कोशिशों के बीच एक बार फिर हिंसा ने सिर उठाया है। बिष्णुपुर जिले में सोमवार सुबह हुए दो लगातार धमाकों ने इलाके में दहशत फैला दी। इन धमाकों में दो स्थानीय लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस के मुताबिक पहला धमाका सुबह करीब 5.45 बजे फौगाकचाओ थाना क्षेत्र के नगौकोंन इलाके में हुआ। यह धमाका एक सुनसान पड़े मकान में हुआ, जहां कथित तौर पर आईईडी लगाया गया था। यह मकान मई 2023 में भड़की

जातीय हिंसा के बाद से खाली पड़ा है और उसका परिवार फिलहाल राहत शिविर में रह रहा है। दूसरा धमाका इसी जगह से करीब 200 मीटर दूर



सुबह 8.45 बजे हुआ, जब पहले धमाके की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग वहां जमा हो गए थे।

सरकारी अस्पताल में भर्ती

धमाकों में सनातोम्बा सिंह और इंदुबाला देवी घायल हुए हैं। दोनों के दाहिने पैर में छर्रे लगे हैं। उन्हें तुरंत

सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है।

एसआईआर के दौरान ‘अमानवीय’ आचरण के खिलाफ अदालत का रुख करूंगी: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किए गए ‘‘अमानवीय या’’ आचरण के खिलाफ अदालत का रुख करेंगी। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से जुड़े भय, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी के कारण कई लोगों की मौत हुई है और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘हम एसआईआर के कारण हुए अमानवीय व्यवहार और

इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के खिलाफ अदालत में कल याचिका दायर करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यदि अनुमति



मिली तो मैं भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एक आम नागरिक के रूप में इस अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैं एक प्रशिक्षित वकील भी हूं।’’

कारणों के मतदाता सूची से नामों को ‘‘मनमाने ढंग से’’ हटाया जा रहा है, जिससे विधानसभा चुनावों से पहले एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया डर पैदा करने वाली प्रक्रिया बन गई है। उन्होंने दावा किया कि गंभीर रोग से ग्रसित लोगों और बुजुर्ग नागरिकों को यह साबित करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर किया जा रहा कि वे वैध मतदाता हैं।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘‘अगर कोई भाजपा नेताओं के बूढ़े माता-पिता को पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दे, तो उन्हें कैसा लगेगा? जब से एसआईआर शुरू हुआ है, डर से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं।’’

सिद्धरमैया सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे

बेंगलुरु। सिद्धरमैया छह जनवरी को कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे डी. देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्होंने सोमवार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय जनता के आशीर्वाद को दिया। उनके और उर्स के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि जहां उर्स शासक वर्ग से संबंधित थे, वहीं वह सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय (कुरुबा या चरवाहा) से आते हैं। उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘जनता के आशीर्वाद से कल (मंगलवार को) कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का दिवंगत डी. देवराज उर्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। गर्व की बात है कि मैं और उर्स दोनों मैसूर से हैं।’’ यह पूछने पर कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह यह रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे तो

सिद्धरमैया ने स्वीकार किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनना तो दूर, मंत्री बनने की भी कल्पना नहीं की थी।

सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘मैंने तो बस यही



सोचा था कि तालुक बोर्ड सदस्य बनने के बाद मैं विधायक बनूंगा। मैं अब तक आठ चुनाव जीत चुका हूं। मैं दो संसदीय चुनाव और दो विधानसभा चुनाव हार चुका हूं। अपने जीवन में मैंने तालुक चुनावों सहित कुल 13 चुनाव लड़े हैं।’’

उन्होंने उर्स से उनकी तुलना के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘देवराज उर्स सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं थे। वास्तव में, वह शासक वर्ग से थे। वह उस समुदाय से थे जिसकी आबादी ज्यादा नहीं थी लेकिन वह एक लोकप्रिय नेता थे।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी और उर्स की कोई तुलना नहीं है। सिद्धरमैया ने कहा कि उर्स का दौर वर्तमान से भिन्न था और देवराज उर्स ने सीधे जनता से धन इकट्ठा कर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, ‘‘1962 में लोगों ने उन्हें धन दिया और उनके पक्ष में मतदान किया। अब समय बदल गया है।’’

उर्स के रिकॉर्ड को तोड़ने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरमैया ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही होते हैं। उन्होंने खेल का उदाहरण देते हुए अपनी इस उपलब्धि की तुलना विराट कोहली द्वारा क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने से की।

दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ताओं-- उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत करते हुए कहा कि शहर को दंगों की आग में धकेलने के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों-- उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया लेकिन ‘‘भागीदारी के स्तर’’ का हवाला देते हुए पांच अन्य को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी.



अंजारिया की पीठ ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

गुप्ता ने यहां ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘‘हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपियों-- शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि दंगों में शामिल लोगों का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए कड़ा संदेश जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ‘‘अपराध में भागीदार’’ थीं। दिल्ली

के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दंगे एक ‘‘सुनियोजित साजिश’’ का नतीजा थे। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली की जनता के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची गई थी। आज के फैसले ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया है।’’ उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्पष्ट संदेश मिलता है कि ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अदालत का यह आदेश देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए एक मिसाल बनेगा। सूद ने कहा, ‘‘सरकार का विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन देश का विरोध करना अलग बात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के खिलाफ काम करने के आरोपियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं।’’

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दंगाइयों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कड़ा संदेश देने के लिए उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया। फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

आचार्य

वाळशास्त्री जांभेकर

(१८१२-१८४६)

संस्मरण

दर्पणकाराचे

- ६ जानेवात्री -

पत्रकार

दिनाच्या

हार्दिक शुभैच्छा!

www.mahasamvad.in

MaharashtraDGIPR

MahaDGIPR

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन

DGIPR/2025-26/5000

स्थानीय निकाय चुनाव में निर्विरोध जीत पर बोले मंत्री बावनकुले- लोकतंत्र के लिए अच्छा

दिव्यांश
मुंबई(संवाददाता)

महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि नगर निगम चुनावों में निर्विरोध जीत लोकतंत्र के लिए अच्छी है। वहीं, विपक्षी दल जो अपने लिए न्याय की मांग करना चाहते हैं, वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। चिकालथाना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि निर्विरोध चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति दी है। बावनकुले की ये टिप्पणियां शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य चुनाव आयोग से 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनावों से पहले 68 नगर निगम वार्डों में सत्तारूढ़ महायुक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित किए जाने के परिणामों को रद्द करने की अपील और इस चेतावनी के बाद



आई हैं कि लोकतंत्र को भीड़तंत्र द्वारा कुचला नहीं जाना चाहिए। राज्य के राजस्व मंत्री ने कहा कि अगर कहीं निर्विरोध चुनाव हो रहे हैं, तो यह एक अच्छी बात है। निर्विरोध जीतने वालों का एजेंडा विकास है। राज ठाकरे ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया

एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवा पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। बावांकुले ने आगे कहा कि

वह एमएनएस चाहें तो अदालत का रुख कर सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। निर्विरोध चुनाव जीतना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जब स्थानीय शासी निकायों और ग्राम पंचायतों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ठाकरे परिवार के चचेरे भाइयों पर कटाक्ष करते हुए बावाकुले ने कहा कि ये दोनों रैलियों में भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये भीड़ वोटों में तब्दील हो। उन्होंने वीबीए नेता शुजात अबेडकर के उस बयान पर भाजपा का रुख भी स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने कहा, 'प्रणिति शिंदे ने अभी तक किसी भी भाजपा नेता से संपर्क नहीं किया है। इस तरह के आरोप लगाकर किसी के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है।'

आयआरसीटीसी पश्चिमी क्षेत्र के एन्चुअल डे पर सम्मानित डायनिंग कार टीम

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आयआरसीटीसी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत डायनिंग कार, मुंबई सेंट्रल की टीम को ग्रुप जनरल मैनेजर, गौरव झा द्वारा सम्मानित किया गया। डायनिंग कार के पर्यवेक्षक और स्टाफ द्वारा राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी जैसी प्रतिष्ठित ट्रेनों में खान पान की गुणवत्ता की जांच की जाती है और इसके साथ साथ ट्रेनों में अति विशिष्ट लोगों के खान पान की सेवा का भी ध्यान रखा जाता है और उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि यात्रियों को खान पान सेवा में कोई दिक्कत न हो, इसके अलावा पर्यवेक्षक स्टाफ को खान पान सेवा की ट्रेनिंग भी देते हैं और खान पान सेवा में सुधार के लिए सुझाव भी देते हैं ताकि ट्रेन में खान पान सेवा और बेहतर हो। किसी कारण बस अगर ट्रेन लेट हो जाती है तब इनकी प्राथमिकता होती है कि यात्रियों के खान पान का पूरा पूरा



खयाल रखा जाए।

गत वर्ष में आयआरसीटीसी पश्चिमी क्षेत्र मुंबई के डायनिंग कार के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट

सेवाओं के लिए उन्हें गौरव झा ग्रुप जनरल मैनेजर, आईआरसीटीसी पश्चिमी क्षेत्र मुंबई द्वारा पुरस्कृत किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल द्वारा नासिक रोड स्टेशन पर व्यापक सुरक्षा निरीक्षण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पूनीत अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), भुसावल मंडल ने मंडल में परिचालन सुरक्षा एवं विश्वसनीयता को और सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों के तहत दिनांक 03.01.2026 को नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर व्यापक सुरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने रूट रिले इंटरलॉकिंग प्रणाली, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय, ईएसएम कार्यालय तथा स्टेशन पर उपलब्ध अन्य संबंधित परिचालन एवं सुरक्षा सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य झूठी पर तैनात कर्मचारियों की तत्परता, सतर्कता तथा निर्धारित सुरक्षा नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा करना था। मंडल रेल प्रबंधक ने कार्यरत कर्मचारियों के साथ विस्तृत संवाद करते हुए दैनिक कार्य में सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन, कार्य अनुशासन तथा



प्रक्रियात्मक अनुपालन के महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों को निरंतर सतर्कता, उचित अभिलेख संधारण, सही सिग्नलिंग एवं त्वरित

प्रतिक्रिया तथा किसी भी असामान्य या आपात स्थिति में तत्काल एवं उपयुक्त कार्रवाई करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया, ताकि सुरक्षित एवं समयबद्ध रेल

परिचालन सुनिश्चित किया जा सके। मंडल रेल प्रबंधक ने सुरक्षा उपकरणों एवं प्रणालियों की स्थिति तथा कार्यक्षमता की भी समीक्षा की। उन्होंने नियमित जांच, कमियों की समय पर रिपोर्टिंग तथा सक्रिय सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने सभी कर्मचारियों से बिना किसी शॉर्टकट के नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया। इस निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी, भुसावल मंडल उपस्थित रहे। उन्होंने सुरक्षा से संबंधित पहलुओं की समीक्षा में सहयोग किया तथा आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रकार के निरीक्षण भुसावल मंडल के सभी स्टेशनों एवं परिचालन इकाइयों में सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं, जिनका अंतिम उद्देश्य यात्रियों एवं माल परिवहन के लिए सुरक्षित, कुशल एवं विश्वसनीय रेल परिचालन सुनिश्चित करना है।

पश्चिम रेलवे
वडोदरा मंडल

ट्रेक रखरखाव गतिविधियों की आउटसोर्सिंग

ई-निविदा सूचना संख्या: DRM-BRC 165 of 2025-26 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (का/ले) वडोदरा द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा संख्या: DRM BRC 165 of 2025-26 कार्य का नाम: BRC-GER सेक्शन: सीनियर D E N / उत्तर/B R C के अधिकार क्षेत्र में SSE (P.Way) MHD के तहत ट्रेक रखरखाव गतिविधियों की आउटसोर्सिंग। कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में): ₹ 5,02,41,941.95 जमा की जाने वाली बोली सुरक्षा (रुपये में): ₹ 4,01,200.00 निविदा जमा करने और खोलने की तारीख और समय: निविदा 27.01.2026 को 15.00 बजे से पहले जमा करनी है, और उसी तारीख को 15.30 बजे खोली जाएगी। वेबसाइट का विवरण और उस स्थान के लिए नोटिस जारी पूरी जानकारी देखी जा सकती है और उस कार्यालय का पता जहां से निविदा फॉर्म खरीदा जा सकता है: मंडल रेल प्रबंधक (WA/C) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-4 वेबसाइट @ www.ireps.gov.in BRC 310

हमें लाइक करें: [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly)

यात्रियों की मांग पर एसएमवीटी बेंगलुरु-बीदर विशेष ट्रेनों की सेवाएं 34 अतिरिक्त फेरों के लिए बढ़ाई गई

सोलापुर मंडल के कलबुर्गी, शाहाबाद एवं वाडी स्टेशनों पर होगा ठहराव

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, रेलवे ने एसएमवीटी बेंगलुरु और बीदर वेड्स बीच संचालित द्विसाप्ताहिक विशेष ट्रेनों की सेवाओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अतिरिक्त 34 फेरों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। एसएमवीटी बेंगलुरु-बीदर द्विसाप्ताहिक विशेष ट्रेनें (34 फेरे) ट्रेन संख्या 06539 (एसएमवीटी बेंगलुरु-बीदर) यह द्विसाप्ताहिक विशेष ट्रेन, जिसे पहले 28.12.2025 तक चलाने की घोषणा की गई थी, अब प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को 27.02.2026 तक चलाई जाएगी।

(कुल 17 फेरे) ट्रेन संख्या 06540 (बीदर-एसएमवीटी बेंगलुरु) यह द्विसाप्ताहिक विशेष ट्रेन, जिसे पहले 29.12.2025 तक चलाने की घोषणा की गई थी, अब प्रत्येक शनिवार और सोमवार को 28.02.2026 तक चलाई



जाएगी। (कुल 17 फेरे) उपरोक्त विशेष ट्रेनों की संरचना (रैंक) एवं ठहरावों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन विशेष ट्रेनों का मध्य रेलवे के सोलापुर

मंडल के तीन स्टेशनों-कलबुर्गी, शाहाबाद और वाडी-पर ठहराव होगा। आरक्षण एवं बुकिंग इन विशेष ट्रेनों के लिए विशेष शुल्क सहित आरक्षण सभी कंप्यूटीकृत आरक्षण केंद्रों एवं www.ircct.co.in वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अनारक्षित कोचों के लिए टिकट बुकिंग स्टेशन स्थित बुकिंग काउंटरों तथा यूटीएस (UTS) मोबाइल ऐप के माध्यम से भी की जा सकती है। यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें। इन विशेष ट्रेनों के ठहरावों एवं विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए यात्री

www.enquiry.indianrail.gov.in पर विजिट करें अथवा RailOne या NTES मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।

पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से दिसम्बर, 2025 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से प्राप्त किया 155 करोड़ से अधिक का जुर्माना एसी उपनगरीय लोकल से प्राप्त किया गया लगभग 3 करोड़ का जुर्माना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे पर निर्बाध, आरामदायक यात्रा एवं बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी बोनाफाइड यात्रियों को मुंबई उपनगरीय, मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में निरंतर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बिना टिकट/अनियमित यात्रा की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की निगरानी में कार्यरत हाई मोटिवेटेड टिकट चेकिंग टीम द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2025 की अवधि के दौरान अनेक टिकट चेकिंग अभियान आयोजित किए गए। इसके परिणामस्वरूप 155.46 करोड़ की राशि की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 49इ अधिक है। इस राशि में मुंबई उपनगरीय

खंड से 41.26 करोड़ की वसूली भी शामिल है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क

हैं, 2.51 लाख मामलों की पहचान के माध्यम से 15.54 करोड़ की राशि वसूल की गई, जो पिछले वर्ष के दिसम्बर माह



अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केवल दिसम्बर माह में ही बिना टिकट/अनियमित यात्रियों, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल

की तुलना में लगभग 42इ अधिक है। इसके अलावा, दिसम्बर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे ने 92 हजार मामलों की पहचान के माध्यम से 3.95 करोड़ की जुर्माना राशि प्राप्त की। एसी

लोकल ट्रेनों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए नियमित रूप से औचक टिकट चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एसी लोकल ट्रेनों में केंद्रित टिकट चेकिंग अभियानों के परिणामस्वरूप अप्रैल से दिसम्बर 2025 की अवधि के दौरान लगभग 91 हजार अनधिकृत यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया तथा 2.97 करोड़ की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 97इ अधिक है। इस प्रकार के उल्लेखनीय परिणाम अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता एवं समर्पण को दर्शाते हैं। पश्चिम रेलवे आम जनता से अपील करती है कि कृपया उचित एवं वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें।

नगरपालिका सार्वत्रिक चुनाव 2025-26

मतदान के दिन 15 जनवरी को मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार दिनांक 15 जनवरी 2026 को राज्य में 29 नगरपालिकाओं के सार्वत्रिक चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इन चुनावों में सभी मतदाता अपने मतदान के अधिकार का सही एवं निर्भीक रूप से प्रयोग कर सकें, इसके लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खनन विभाग द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2025 को एक शासकीय परिपत्र जारी किया गया है। इस परिपत्र में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं- पहला, जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां कार्यरत सभी श्रमिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, भले ही वे कार्य के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत हों, मतदान के

दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पूर्ण वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। दूसरा, यह सार्वजनिक अवकाश उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू रहेगा। इसमें सभी कारखाने, निर्जी एवं सार्वजनिक संस्थान, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, आवासीय होटल, भोजनालय, अन्य सेवा संस्थान, चलचित्रगृह, व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियां, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां, शॉपिंग सेंटर, मॉल, खुदरा विक्रेता तथा अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं। तीसरा, विशेष परिस्थितियों में जहां पूर्ण दिवस अवकाश देने से भारी नुकसान होने की आशंका हो, अथवा जो प्रतिष्ठान अत्यावश्यक सेवाओं या जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित हों, वहां अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को पूरे दिन का अवकाश देना

संभव न होने की स्थिति में मतदान के लिए दो से तीन घंटों की विशेष छूट दी जाएगी, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक अथवा प्रबंधन की होगी। चौथा, उपर्युक्त उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों और दुकानों के मालिकों एवं प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी मतदाता को मतदान हेतु दिया गया अवकाश या छूट प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यह आदेश राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने तथा अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

कांदिवली-बोरीवली सेक्शन में 6वीं लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली-बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य के संबंध में 20/21 दिसम्बर, 2025 की रात्रि से 18 जनवरी, 2026 तक कुल 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 06/07 जनवरी, 2026 की रात्रि में कांदिवली पर अप फास्ट लाइन पर प्लाईट संख्या 103 के इन्सर्शन हेतु एक मेजर ब्लॉक

लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइन पर 00:00 बजे से 05:30 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00

के कारण कुछ उपनगरीय ट्रेन सेवाएं निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण



बजे से 04:30 बजे तक रहेगा। उपर्युक्त ब्लॉकों एवं 5वीं लाइन के निलंबन

प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक-I एवं II में दी गई है।

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य				
ई-निविदा सूचना संख्या DRM-BRC 161 से 164 वर्ष 2025-26				
भारत के राष्ट्रपति की ओर से डिवाइज रेलवे मैनेजर (WA/C), वेस्टर्न रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390004 द्वारा नीचे दिए गए कामों के लिए सीलबंद ई-निविदा मंगाए गए हैं।				
क्र. सं.	निविदा संख्या	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में)	जमा की जाने वाली बोली सुरक्षा (रुपये में)
1	DRM BRC 161 of 2025-26	वडोदरा मंडल:- वडोदरा मंडल में फ्लैश बट वेल्ड्स का फेज्ड एर्रे USFD टेस्टिंग (PAUT)।	9,75,05,556.00	6,37,500.00
2	DRM BRC 162 of 2025-26	वडोदरा मंडल:- सीनियर DEN साउथ BRC के अधिकार क्षेत्र में साइज (M-25) और (M-27) के लिए सिंगल पीस स्प्रिंग इंस्टैंड रियूजेबल सेल्फ लॉकिंग स्टील नट्स उपलब्ध कराना और लगाना (पुनर्आमंत्रित) (R-2)।	2,58,16,324.54	2,79,100.00
3	DRM BRC 163 of 2025-26	उत्तराण:- नए HL PF, UP PF का विस्तार, स्टेशन बिल्डिंग और अन्य यात्री सुविधाएं प्रदान करना।	22,37,97,934.61	12,69,000.00
4	DRM BRC 164 of 2025-26	(ब्रिज जॉन नंबर 20 का 2025-26) - नए काम और सभी सामान्य मरम्मत और रखरखाव का काम, प्रत्येक 5,00,000.00 रुपये तक, जिसमें ADEN नाडियाद के अधिकार क्षेत्र में रोड ओवर ब्रिज सहित ब्रिज का काम शामिल है (पुनर्आमंत्रित) (R-1)।	76,43,020.00	1,52,900.00
निविदा प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की तिथि एवं समय: निविदा दिनांक 22.01.2026 को 15.00 बजे से पहले प्रस्तुत की जानी है तथा उसी तिथि को 15.30 बजे खोली जानी है।वेबसाइट विवरण तथा उस स्थान के निर्देश जहां पूर्ण विवरण देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है कार्यालय का पता: वेबसाइट: www.ireps.gov.in . मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए/सी) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004.				
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly				

कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी सौंपे गई जिम्मेदारी का निर्वहन करे - जिलाधिकारी राहुल कर्डिले

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नांदेड़। ‘हिंद-दी-चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समगम वर्ष के अवसर पर नांदेड़ में दिनांक 24 और 25 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, गुरुद्वारा प्रशासन तथा विभिन्न समाजों के अशासकीय सदस्यों की सहभागिता से कुल 25 समितियों का गठन किया गया है। कार्यक्रम को अत्यंत अनुशासित, सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रत्येक समिति को अपनी निर्धारित जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और समयबद्ध तरीके से निभानी चाहिए, ऐसा आह्वान राहुल कर्डिले ने किया। वे ‘हिंद-दी-चादर’ कार्यक्रम के संदर्भ में गठित समितियों की विस्तृत समीक्षा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन सभागृह में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डॉ. रत्नाकर गायकवाड़, निवासी उपजिलाधिकारी किरण अंबेकर, मुख्यमंत्री कार्यालय के जगदीश



उपस्थित थे। नांदेड़ में यह कार्यक्रम राज्य शासन के अल्पसंख्यक विभाग, ‘हिंद-दी-चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 350वीं शहीदी समगम समिति तथा सिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, मोहियाल, सिंधी, वाल्मीकि, उदासीन संप्रदाय और भगत नामदेव वारकरी समाज के संयुक्त तत्वावधान में मामा चौक स्थित

सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए नांदेड़ जिले सहित कड़ेवाले, संबंधित विभागों के अधिकारी, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और सदस्य

संभावना है। इसी पृष्ठभूमि में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियों की जा रही हैं और संपूर्ण नियोजन के लिए 25 समितियों की स्थापना की गई है। जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने निर्देश दिए कि सभी समिति प्रमुख और उनके सहयोगी अपनी जिम्मेदारियों का समय पर और पूर्ण योजना के साथ निर्वहन करें।

कार्यक्रम नियोजन के लिए गठित समितियां इस प्रकार हैं— जागरण व्यवस्थापन समिति, मैदान व्यवस्थापन समिति, मंडप व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा व्यवस्थापन समिति, स्वयंसेवक व्यवस्थापन समिति, अतिथि स्वागत समिति, लंगर एवं भोजन व्यवस्थापन समिति, स्वच्छता व्यवस्थापन समिति, चिकित्सा सेवा समिति, विद्युत एवं ध्वनि व्यवस्थापन समिति, प्रचार एवं मीडिया समिति, कार्यक्रम प्रस्तुति समिति, ध्वज एवं सजावट समिति, वित्तीय व्यवस्थापन समिति, शासकीय अनुमति समिति, जुताघर व्यवस्थापन समिति, जलापूर्ति समिति, महिला सेवा समिति, वरिष्ठ नागरिक समिति, जिला समन्वय समिति, स्वरूपा व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा एवं जांच समिति, निवास व्यवस्थापन समिति, प्रदर्शनी समिति तथा आरक्षित समिति। इन सभी समितियों में शासकीय अधिकारी, गुरुद्वारा प्रशासन के प्रतिनिधि और विभिन्न समाजों के अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सभी के सामूहिक सहयोग से ‘हिंद-दी-चादर’ शहीदी समगम कार्यक्रम को यादगार और ऐतिहासिक बनाने का विश्वास इस अवसर पर व्यक्त किया गया।

‘दिलखुलास’ कार्यक्रम में डॉ. हितेश सिंघवी की विशेष बातचीत

मुंबई। सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय द्वारा निर्मित आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘दिलखुलास’ में मुख एवं सिर-गर्दन कैंसर : लक्षण, निदान और रोकथाम के उपाय विषय पर एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में मुख एवं सिर-गर्दन कैंसर शल्य चिकित्सा (ऑन्को-सर्जरी) के विशेषज्ञ डॉ. हितेश सिंघवी ने इस गंभीर बीमारी से जुड़ी महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी साझा की है। यह विशेष साक्षात्कार 7 से 12 जनवरी 2026 के दौरान प्रतिदिन प्रातः 7.25 बजे से 7.40 बजे तक आकाशवाणी के सभी केंद्रों से तथा News on AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इस साक्षात्कार का संचालन उद्घोषिका सुचिता गरुड़े द्वारा किया गया है। डॉ. हितेश सिंघवी ने बताया कि सिर और गर्दन का कैंसर एक गंभीर एवं जटिल रोग है, जो मुख गुहा, गला, स्वरयंत्र, लार ग्रंथियां, नाक, साइनस तथा लिम्फ नोड्स सहित सिर-गर्दन क्षेत्र के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर यह बीमारी एक बड़ी

चुनौती बनती जा रही है और हर वर्ष इसके रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। यह कैंसर रोगियों की बोलने, निगलने और श्वसन क्षमता के साथ-साथ चेहरे की बनावट और दैनिक जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा प्रभाव डाल

के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी संदर्भ में डॉ. सिंघवी ने मुख एवं सिर-गर्दन कैंसर के शुरुआती लक्षणों, समय पर कराई जाने वाली जांचों तथा इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक रोकथाम उपायों पर वैज्ञानिक और सरल भाषा में विस्तृत



सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बीमारी का समय पर निदान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर उपचार अधिक प्रभावी सिद्ध होता है और जटिलताओं

जानकारी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रम के माध्यम से दी है। यह कार्यक्रम आम नागरिकों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और गंभीर बीमारियों के प्रति समय रहते सावधानी बरतने के उद्देश्य से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

चुनाव ड्यूटी में कोर्ट स्टाफ की तैनाती पर हाईकोर्ट सख्त, बीएमसी आयुक्त की गलती पर लगाई फटकार

मुंबई। चुनाव ड्यूटी के लिए अदालतों के कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आयुक्त भूषण गगरानी को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद आयुक्त ने खुद स्वीकार किया कि कोर्ट स्टाफ को चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाना उनकी गलती थी। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड़ की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीएमसी आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जारी किए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा आपको खुद को बचाना चाहिए। आपके पास कोर्ट कर्मचारियों को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्वतः संज्ञान लेते हुए बीएमसी आयुक्त द्वारा अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाने संबंधी सभी पत्रों पर रोक लगा दी थी। साथ ही आयुक्त को निर्देश दिया गया था कि

वह हाईकोर्ट या अधीनस्थ अदालतों के किसी भी कर्मचारी से चुनाव ड्यूटी के लिए संपर्क न करें। सोमवार को सुनवाई के दौरान बीएमसी

ने स्पष्ट फैसला लिया था कि हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के सभी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत



आयुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रवि कदम ने अदालत को बताया कि आयुक्त ने अपने आदेश वापस ले लिए हैं। इसके बाद कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अब चुनावों के लिए अन्य स्रोतों से व्यवस्थाएं की जाएं। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2008 में हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति

अधीनस्थ अदालतों और उनके कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण हाईकोर्ट का ही होता है। हाईकोर्ट ने मामले की आली सुनवाई चुनावों के बाद तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन साथ ही यह साफ संदेश दे दिया है कि न्यायिक व्यवस्था में किसी भी तरह का प्रशासनिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नांदेड़। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ‘हिंद-दी-चादर’ कार्यक्रम की शुरुआत के तहत ‘आरंभता की अरदास’ का विधिवत आयोजन हाल ही में नांदेड़ स्थित लोक निर्माण विभाग के मैदान में अत्यंत श्रद्धा और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा के पंचप्यारे द्वारा मुख्य कार्यक्रम पंडाल का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहयाल, वाल्मीकि, भगत नामदेव संप्रदाय तथा उदासी संप्रदाय के संत-महंत और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ‘हिंद-दी-चादर’ कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, अबचलनगर, नांदेड़ के मुख्य ज्येष्ठदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाई जोसिंदर सिंह जी, भाई राम सिंह जी, भाई कश्मीर सिंह जी, भाई गुरमीत सिंह जी तथा गुरुद्वारा लंगर साहिब के संत बाबा बलविंदर सिंह जी भी उपस्थित

रहे। इस कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य बाबू सिंह महाराज (पोहरादेवी), जिलाधिकारी राहुल कर्डिले, पुलिस अधीक्षक अभिनाश कुमार, निवासी

के अध्यक्ष डॉ. विजय सतबीर सिंह, सरजीत सिंह मील, क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी तथा राज्य स्तरीय समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। समन्वयक रमेश्वर नाइक ने बताया

किया जाएगा। यह पहल अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा नौ विभिन्न समुदायों की संयुक्त सहभागिता से क्रियान्वित की जा रही है। इस अवसर पर गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक डॉ. विजय सतबीर सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के महान बलिदान को स्मरण किया जाएगा और उनकी गौरवशाली गाथा आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नांदेड़ सहित आसपास के सभी नागरिकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाएं। रविवार, 25 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा कार्यक्रम स्थल से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।



उपजिलाधिकारी किरण अंबेकर, तहसीलदार संजय वरकड, 350वीं शहादत समगम समिति के समन्वयक रमेश्वर नाइक, महंत सुनील महाराज, महंत जितेंद्र महाराज, क्षेत्रीय समिति

करुणा और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ नववर्ष की शुरुआत : मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, भुसावल के दो महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपक्रम

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ नववर्ष की शुरुआत करते हुए, मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, भुसावल ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान तथा समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, भुसावल की अध्यक्षा एवं संगठन की सदस्यों ने जळगांव जिले के जमुंजिरा गांव का दौरा कर आदिवासी समाज के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस उपक्रम के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं को सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया, जिससे मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य, स्वच्छता जागरूकता एवं सम्मान को बढ़ावा मिला। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा यह महत्वपूर्ण विषय प्रायः



वितरण किया गया, जिससे आदिवासी समुदाय को तात्कालिक पोषण सहायता प्राप्त हुई। इस पहल से स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार, जागरूकता में वृद्धि तथा समुदाय के साथ विश्वास और सहभागिता को सुदृढ़ करने में

सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है। यह उपक्रम जमीनी स्तर पर देखभाल, समावेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व को रेखांकित करता है।

इसी क्रम में, मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, भुसावल ने अध्यक्ष श्रीमती रेखा अग्रवाल के मार्गदर्शन में क्षितिज स्पेस्टिक सेंटर में गणवेश वितरण का एक सार्थक उपक्रम भी आयोजित किया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों

को प्रदान किए गए ये गणवेश केवल वस्त्र नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और प्रोत्साहन के प्रतीक हैं। इस पहल से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उनमें अपनत्व की भावना विकसित होती है तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु अनुकूल और समावेशी वातावरण के निर्माण में सहायता मिलती है। ऐसे उपक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके अधिक आत्मविश्वासपूर्ण एवं संतोषजनक जीवन-प्रवास को समर्थन प्रदान करते हैं। इन उपक्रमों के माध्यम से मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, भुसावल ने सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और समावेशी देखभाल के प्रति अपनी

प्रतिबद्धता को एक बार फिर स्पष्ट किया है तथा यह संदेश दिया है कि नववर्ष की शुरुआत अर्थपूर्ण कार्यों और समाज पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालने वाली पहलों के साथ की गई है।

दिव्यांग व्यक्तियों को दिए जाने वाले वैश्विक पहचान पत्र की जांच सुनिश्चित की जाए- सचिव तुकाराम मुंढे

मुंबई। दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला वैश्विक दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) शासकीय एवं अर्धशासकीय सेवाओं में आरक्षण, विभिन्न सरकारी योजनाओं, आर्थिक रियायतों तथा अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। परंतु हाल के दिनों में कुछ स्थानों पर फर्जी अथवा गलत चिकित्सीय जांच रिपोर्ट के आधार पर यूडीआईडी कार्ड प्राप्त किए जाने के मामले सामने आए हैं। इससे वास्तविक दिव्यांग व्यक्तियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए यूडीआईडी कार्ड जारी करने से पूर्व

संबंधित चिकित्सीय जांच रिपोर्ट की जांच सुनिश्चित की जाए- सचिव तुकाराम मुंढे ने कहा। सचिव मुंढे ने स्पष्ट किया कि गलत अथवा फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र लेना या देना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि कुछ मामलों में

अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण एवं वाणी विधिवत जांच और सत्यापन संबंधित संस्थान के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, ऐसा निर्देश दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे ने दिया है। सचिव मुंढे ने स्पष्ट किया कि गलत अथवा फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र लेना या देना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि कुछ मामलों में

उक्त संस्थान के माध्यम से जारी होने का दावा करती हैं, उनकी जांच और सत्यापन के लिए अनिवार्य रूप से संस्थान के आधिकारिक ई-मेल पते ayjnihh-mum@nic.in पर भेजी जाएं। सचिव तुकाराम मुंढे ने सभी संबंधित कार्यालयों और प्राधिकरणों से अपील की है कि वे इस निर्देश के अनुसार तत्काल कार्रवाई करें तथा गलत जानकारी देकर दिव्यांगता प्रमाणपत्र या किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त न किया जाए। इससे वास्तविक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी किया, चार साल पहले पत्नी की हत्या का लगा था आरोप

ठाणे की एक अदालत ने 2021 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी 32 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साक्ष्यों पर आधारित इस मामले में दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक बुनियादी तथ्यों को साबित करने में असफल रहा। प्रधान अग्रवाल एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने शनिवार को अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह परिस्थितियों की कड़ी में शामिल प्रत्येक तथ्य को साबित करे। जो केवल

इस परिकल्पना की ओर ले जाता है कि आरोपी दोषी है और उसकी निर्दोषता की कोई संभावना नहीं है। पत्नी का सिर बाथरूम के फर्श पर पटकने का आरोप अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 9 मई, 2021 को शान मोहम्मद शाबिद अली खान ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दाइघर स्थित अपने आवास पर अपनी चौथी पत्नी अरफा खान की हत्या कर दी थी। आरोप है कि खान को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। उसने

पत्नी का सिर बाथरूम के फर्श पर पटक दिया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं और चेहरे की हड्डियां टूट गईं। कुछ पड़ोसियों ने अरफा को खून से लथपथ पाया, और उसका दो साल का बच्चा उसके शव पर रो रहा था। हत्या के तहत मामला दर्ज था खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाया गया था और वह 9 जून, 2021 से जेल में है। हालांकि पीडित की मेडिकल रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि की।

सम्पादकीय

जवाबदेही के बजाए दिया जा रहा मुआवजा, मंत्री और सरकार का रवैया अफसोसजनक

इंदौर में पेयजल दूषित होने की वजह से कई लोगों की मौत के बाद राहत के तौर पर सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन सवाल है कि क्या कुछ रस्मी औपचारिकताएं पूरी करना इस समस्या का हल हो सकता है। सबसे जरूरी था कि इस घटना के बाद निचले स्तर के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के संमांतर शीर्ष स्तर पर बरती गई लापरवाही के लिए भी ज़िम्मेदारी तय की जाती। मगर ऐसा लगता है कि इसे किसी सामान्य हादसे की शकल में देखा जा रहा है। वरना क्या कारण है कि इतने गंभीर मामले के बाद भी सरकार के रवैये में एक अफसोसनाक उदासीनता दिख रही है।

इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय वहां के एक मंत्री सवालों को जिस तरह बेमानी बता रहे थे, उसमें एक विचित्र उपेक्षाभाव था। अब्ल तो पेयजल जैसी सबसे बुनियादी ज़रूरत के पूरी तरह सुरक्षित होने को लेकर सरकार अपनी ओर से सजग रहती, लेकिन इसके बजाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा है कि प्रभावित इलाके में पीने के पानी के अतिरिक्त टैंकर भेजे जाएं।

इस घटना से फिर यही जाहिर हुआ है कि महज हादसा या चूक मानी जाने वाली कई घटनाएं अक्सर अधिकारियों की अदूरदर्शिता, लंबे समय से बरती जाने वाली लापरवाही और कई बार जानबूझ कर की गई उपेक्षा का नतीजा होती हैं। इंदौर के जिस इलाके में पेयजल दूषित होने की घटना सामने आई, क्या ऐसा अचानक हो गया होगा? अगर फिलहाल आई खबरों पर ही भरोसा किया जाए कि पानी की आपूर्ति वाले पाइप में गंदे नाले का पानी मिल गया, तो इस पर निगरानी रखना किसकी जिम्मेदारी है? एक बार पेयजल की पाइप बिछ देने के बाद उसमें पानी आ रहा है या नहीं या फिर वह पीने के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है, इसकी नियमित जांच करने, गड़बड़ियों की निगरानी करने का दायित्व किस पर है?

अगर संबंधित महकमे में निचले स्तर पर तैनात कर्मचारी लापरवाही बरत रहे थे, तो इसका ध्यान रखना किसका काम था? इस गंभीर घटना के बाद सवाल उठने और कठघरे में खड़ा किए जाने के बाद जहां सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर सख्त संदेश देने वाली कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां उसके मंत्री संवेदनहीन, अवांछित और गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे थे। अफसोस की बात यह भी है कि इस समूचे मामले में केंद्र सरकार ने एक तरह से विचित्र चुप्पी साधे रखी और उसकी ओर से कुछ नहीं किया गया। जबकि पिछले कई वर्षों से स्वच्छता के लिए तमना जीतने वाले इंदौर में दूषित पेयजल से जिस तरह की त्रासद घटना सामने आई, वैसे में पीड़ित परिवारों से लेकर देश भर के आम लोग यह उम्मीद करते हैं कि इसकी गंभीरता के महेनजर केंद्र सरकार दखल देगी।

दरअसल, ऐसे नाजुक मौकों पर सबसे ज्यादा जरूरी रह होता है कि सरकार आम लोगों के प्रति संवेदनशील दिखे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने का भरोसा दे। मगर कम से कम इस मामले में सच यह है कि लोगों का सरकार पर से भरोसा बुरी तरह टूटा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि राष्ट्रीय स्तर पर ‘हर घर नल जल’ योजना के तहत सभी नागरिकों को पीने का स्वच्छ और शुद्ध पानी मुहैया कराने के दावे किए जाते रहे हैं। मगर पेयजल को लोगों तक पहुंचाने के रास्ते में अगर किसी भी वजह से ऐसी लापरवाही होती है कि उससे लोगों की जान पर खतरा आ जाए, तो ऐसे दावों को किस तरह देखा जाएगा।



ईरान के जेन-जेड प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी सहानुभूति के वैश्विक मायने

ईरान वेड जेन-जेड प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी सहानुभूति के वैश्विक मायने बड़े ही खतरनाक हैं। लिहाजा यदि समय रहते ही एशियाई देश नहीं चेतें तो वे सब धीरे-धीरे अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतियों के सहज शिकार बन सकते हैं। पहले बंगलादेश, फिर नेपाल और अब ईरान में हुए जेन-जेड प्रदर्शन वाकई अमेरिकी डीप स्टेट की उन छिपी हुई मंशाओं को उजागर करते हैं, जिसका उद्देश्य चीन और रूस के सदाबाहर मित्र भारत को कमजोर करना है क्योंकि ये दोनों अमेरिका की वैश्विक दादागिरी की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पहले तो अमेरिका ने इन्हें यानी चीन-भारत को पटाकर और भारत-चीन को परस्पर उलझाकर अपने चिर शत्रु देश रूस को और अधिक कमजोर की कोशिशें की, लेकिन जब वो अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हुआ तो इनके पड़ोस में ‘भारत विरोध’ को हवा दिलवानी शुरू कर दी। इसलिए बंगलादेश व नेपाल न सही, लेकिन ईरान में भारत, चीन और रूस को अविच्छंभ हस्तक्षेप करना चाहिए और कथित लोकतंत्र के नाम पर अमेरिकी थानेदारी का कड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध करना चाहिए, अन्यथा अमाला नम्बर अब उन्हीं का आएगा।

देखा जाए तो ईरान में रोजगार और बढ़ती महंगाई को

लेकर बीते पांच दिनों से जारी जेन-जेड के विरोध प्रदर्शनों ने अब हिसक रूप अखियाार कर लिया है। लिहाजा, ईरानी सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसमें अबतक सात प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और कड़ियों के घायल होने की पुष्टि हुई है। वहीं, इससे व्याकुल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ पर लिखा है कि, ‘अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है तो हम बचाने को तैयार हैं।’

वैश्विक कूटनीतिज्ञों का मानना है कि अमेरिकी नेतृत्व द्वारा दिया गया उक्त बयान ईरान में लोकतंत्र की हिफाजत के बहाने वहां लगी आग में घी डालने जैसा है, जो निंदनीय भी है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी अब डीप स्टेट के समक्ष घुटने टेक चुके हैं और इसकी तथाकथित कारगुजारियों को बढ़ावा देने लगे हैं, जो वाकई दिलचस्प है।

हालांकि, इस अमेरिकी दुस्साहस पर पलटवार करते हुए ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि, ‘ईरान की सुरक्षा रेड लाइन है।’ ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने कहा कि- ‘अमेरिका और इसाइल प्रदर्शन भड़का रहे हैं। अमेरिकी दखल से अशांति फैल जाएगी, उन्हें अपने सैनिकों की फाक करनी चाहिए।’ कहने का तातपर्य यह हुआ कि यदि

अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान उसके खाड़ी देशों और अरब देशों में स्थित सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। पिछले वर्ष वह ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान ऐसा कर भी चुका है, जिसके बाद घबराहट में अमेरिका ने उस युद्ध को मध्यस्थता करके बंद करवाया था।

स्वाभाविक सवाल है कि ईरानी प्रदर्शनकारियों के जिस तरह के उग्र विडियो सामने आए हैं, जहां प्रदर्शनकारी ईरान की सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी करते देखे गए, उसके दृष्टिगत ईरानी सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई करके अपने राष्ट्रीय धर्म का पालन किया है। अन्यथा बंगलादेश व नेपाल की तरह वो सुरक्षाकर्मी भी घुटने टेक सकते थे। हालांकि उन्होंने यह सख्ती दो तीन दिन प्रदर्शनकारियों को झेलने के बाद दिखाई है।

इसलिए डॉनल्ड ट्रंप का यह कहना कि, ‘ईरान का रिवाज मानना है!’, न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। उनकी यह टिप्पणी कि, ‘अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद को आगे बढ़ने के लिए तैयार है’, प्रथमदृष्टया ईरान के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है। इससे जाहिर है कि अब वो भी उस डीप स्टेट के हाथों खेलने को अभिशप्त हैं, जिसका विरोध उन्होंने खुद ही खुफिया कार्यों में स्थिरता और खुरफिया कार्यों में स्थिरता प्रदान करते थे। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप जैसे नेता इसे अपना दुश्मन मानते आये हैं और इसका विरोध करते रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप (2025 में पुनः शपथग्रहण के बाद) कहीं इसे

और उसे पुनः पारसी देश बनाने की चाल चल रहे हैं, यक्ष प्रश्न है।

ऐसा इसलिए कि अमेरिकी डीप स्टेट एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो संतीय एजेंसियों जैसे सीआईए, एफबीआई और एनएसए के गुप्त नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह कथित रूप से चुनी हुई सरकार के समानांतर सत्ता संघालित करता है। जहां तक डीप स्टेट की परिभाषा का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए कि यह शब्द 1990 के दशक में तुर्की से उत्पन्न हुआ और अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में लोकप्रिय हुआ। क्योंकि तब ट्रंप ने इसे रूस की जांच और अन्य विपत्तियों के लिए इस्तेमाल ठहराया। सच कहूं तो यह नेटवर्क विनीय, औद्योगिक हितों के साथ मिलकर निर्वाचित नेताओं को प्रभावित करता है।

ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति इसे क्यों संरक्षण देते हैं? तो इसका माकूल जवाब हम आम व खास धारणा है कि कुछ प्रशासनों (जैसे- जो बाइडन प्रशासन के द्वारा) को डीप स्टेट का संरक्षण प्राप्त होता है क्योंकि यह विदेश नीति प्रदान करता है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप जैसे नेता इसे अपना दुश्मन मानते आये हैं और इसका विरोध करते रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप (2025 में पुनः शपथग्रहण के बाद) कहीं इसे

कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं शह देते नजर आ रहे हैं। इससे वह अपने ही उद्देश्य में विफल साबित हुए।

आपने देखा होगा कि भारत में विगत तीन पारियों से केंद्रीय सत्ता पर काबिज भाजपा ने भी डीप स्टेट पर मोदी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था, जबकि डीप स्टेट मुख्यतः षड्यंत्र सिद्धांत है। कई अमेरिकी सर्वे में वहां के आधे लोग इसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। कहना न होगा कि डीप स्टेट की अवधारणा मूल रूप से एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो गुप्त शक्तियों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है। इसका आधुनिक इतिहास तुर्की से जुड़ा है, जहां 1990 के दशक में ‘डेरिन देवलेट’ (गहरा राज्य) शब्द का इस्तेमाल सेना, खुफिया एजेंसियों और अपराधी तत्वों के गठजोड़ के लिए हुआ।

जहां तक इससे उद्भव की बात है तो इसका प्रारंभिक चरण तुर्की में 1990 के दशक के एक सड़क हादसे से लोकप्रिय हुआ, जिसमें आ राजनेता, पुलिस अधिकारी और माफिया डॉन की मौत हुई। इससे कथित गुप्त गठबंधन यानी डीप स्टेट की चर्चा शुरू हुई। फिर अमेरिका में ओबामा प्रशासन के दौरान इसका छिप्टा बढ़ा, लेकिन डॉनाल्ड ट्रंप ने 2017 से इसे मुख्यधारा में लाकर सीआईए और एफबीआई जैसी एजेंसियों को निशाना बनाया।

जहां तक अमेरिकी संदर्भ में इसके विकास की बात है तो ट्रंप के

पहले कार्यकाल में डीप स्टेट को रूस की जांच और अन्य घटनाओं से जोड़ा गया। 2017-18 के सर्वे में लगभग आधे अमेरिकियों ने इसके अस्तित्व में विश्वास जताया। कुछ सिद्धांतकार इसे रोथ्सवाइल्ड, रॉकफेलर जैसे वित्तीय समूहों से जोड़ते हैं, जो 18वीं सदी से बैंकिंग के माध्यम से प्रभाव डालते रहे।

जहां तक डीप स्टेट के वैश्विक प्रसार की बात है तो यह तुर्की से निकलकर यह मिस्र, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में फैला। भारत में भाजपा ने 2024 में इसे मोदी सरकार के खिलफ साजिश से जोड़ा। हालांकि, कतिपय विद्वान इसे अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धांत मानते हैं क्योंकि वो खुद किसी न किसी रूप में डीप स्टेट से लाभान्वित हैं। वास्तव में डीप स्टेट एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो सरकारी, सैन्य, खुफिया एजेंसियों और कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के गुप्त नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह नेटवर्क लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के बाहर काम करता है और नीतियों को प्रभावित कर का दावा किया जाता है।

मसलन, डीप स्टेट शब्द तुर्की के ‘डेरिन देवलेट’ से लिया गया है, जो गैर-निर्वाचित तत्वों के समूह को दर्शाता है। यह समूह अपने विशेष हितों, जैसे सुरक्षा या आर्थिक एजेंडे, को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से सक्रिय रहता है। वहां का पेंटागन, हथियार निर्माता कंपनियां, नौकरशाही और वित्तीय अभिजात यानी बड़े कॉर्पोरेट्स, बैंकिंग समूह जैसे रॉकफेलर या रोथ्सवाइल्ड भी इससे

जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, गूगल, फेसबुक जैसे टेक दिग्गज और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे एनजीओ भी इसके पार्ट समझे जाते हैं। नौकरशाह और पूर्व अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, खुफिया अधिकारी जो वैचारिक प्रतिबद्धताओं से प्रेरित रहते हैं, इसके अंग बन हैं। वहीं वहां के

वित्तीय परिवार जैसे रोथ्सवाइल्ड, रॉकफेलर जैसे समूह, जो बैंकिंग और परोपकार के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। वहां की सिविल सोसायटी यानी मीडिया, प्रोफेसर, कलाकार और एनजीओ कार्यकर्ता जो मानवाधिकार या पर्यावरण के नाम पर सक्रिय रहते हैं। इसके संचालन का तरीका भी गजब है। ये समूह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बायपास कर शासन परिवर्तन या अस्थिरता पैदा करते हैं। भारत में इन्हें अर्बन नक्सल या राष्ट्रविरोधी इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। यह लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर रहता है और निर्वाचित नेताओं को कमजोर करने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि, कई विशेषज्ञ इसे अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। बताया जाता है कि अमेरिका के आर्थिक और कॉर्पोरेट हित डीप स्टेट के सिद्धांत में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जहां इन्हें गुप्त नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये हित सरकारी नीतियों को प्रभावित कर लाभ कमाते हैं। वहां से कॉर्पोरेट जुड़ाव रखने वाले यानी कॉर्पोरेट दिग्गज जैसे गूगल, फेसबुक और हथियार कंपनियां

डेटा गोपनीयता, कराधान तथा बाजार विनियमन पर प्रभाव डालती हैं। ये शक्तिशाली इकाइयां खुफिया एजेंसियों के साथ साझेदारी कर आर्थिक नीतियों को आकार देती हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे संगठन शासन परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं।

इसका आर्थिक प्रभाव निर्णायक होता है। वहां के वित्तीय परिवार जैसे रोथ्सवाइल्ड और रॉकफेलर बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण के माध्यम से प्रमुख घटनाओं जैसे एशियाई वित्तीय संकट को प्रभावित करते हैं। ये समूह मुक्त बाजार, व्यापार वार्ता और शॉक थेरेपी जैसी नीतियों को प्रोत्साहित कर विकासशील देशों में बाजार पहुंच सुनिश्चित करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे उदाहरण स्टॉक बाजार अस्थिरता पैदा करते हैं। परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। ये हित सैन्य-औद्योगिक परिसर के साथ मिलकर युद्ध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जहां कॉर्पोरेट फंडिंग राजनीतिक प्रभाव खरीदती है। भारत जैसे देशों में एनजीओ वित्तपोषण कोयला परियोजनाओं का विरोध करता है, जो जीडीपी वृद्धि के 2-3% नुकसान पहुंचाता है।

इसलिए इनके कारनामों से शेष दुनिया के लोगों को सवधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गरीब व विकासशील देशों के धनलोलुप नेता व चतुरसुजान अब इनके अंग बन चुके हैं। भारत, चीन व रूस में भी इनकी अचूख खासी तादात होने की अटकलें हैं।

1000 साल पुराने हमलों के बाद भी वैभव के साथ खड़ा है सोमनाथ मंदिर, देश को भी संकल्प की जरूरत

सोमनाथ... ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता हैष्ठ सौराष्ट्रे, सोमनाथं चष्ठयानि ज्योतिर्लिंगां में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है:

‘सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्’

अर्थात सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्त्व रखता है क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था।

सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार

वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनःनिर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का वर्ष भी है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण समप्त हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे।

1026 में एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण, वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं, ये ऐसा दुःख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इसका उस दौर में भारत पर और लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्त्व बहुत ज्यादा था। ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचता था। ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत शक्ति थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर-दूर तक ले जाते थे।

सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज में पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता

सहानुभूति तक सीमित हो गई संवेदना, ठहर गया है सामाजिक आचरण

प्रतिक्रियाओं तक सीमित रह जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित सामाजिक और आर्थिक रपटें बताती हैं कि असमानता और वंचना आज भी व्यापक है, फिर भी अधिकांश मामलों में हमारी भूमिका केवल चिंता व्यक्त करने तक सिमट जाती है। असल में सहानुभूति हमें भावनात्मक संतोष देती है, पर व्यावहारिक जिम्मेदारी का बोध नहीं कराती।

आदिवासी समाज इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 फीसद हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है, लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों में उनकी हिस्सेदारी अनुपात से कहीं अधिक रही है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बड़े

बांधों, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों में लगभग चालीस फीसद तक आदिवासी समुदायों से आते हैं। यह तथ्य केवल विस्थापन का नहीं, बल्कि संस्कृति, आजीविका और सामाजिक पहचान के टूटने का भी संकेत देता है। सहानुभूति के रूप में मुआवजे और पुनर्वास की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन समानुभूति तभी होती, जब नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और विकास को उनके जीवन-संदर्भ से जोड़कर देखा जाए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी यही अंतर स्पष्ट दिखाई देता है।

युनिसेफ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं की रपटें बताती हैं कि आर्थिक और

सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर अब भी चिंता का विषय है, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में। सहानुभूति के तौर पर छात्रवृत्तियां, मध्याह्न भोजन और योजनाएं मौजूद हैं, पर समानुभूति तब सामने आती है जब शिक्षा व्यवस्था यह स्वीकार करती है कि भाषा, गरीबी और परिवारिक जिम्मेदारियां सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जब शिक्षक और व्यवस्था बच्चे की फूटभूमि को समझकर अपनी पद्धति में बदलाव करते हैं, तभी शिक्षा वास्तव में समावेशी बनती है।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन भी हमारे सामाजिक आचरण की परीक्षा लेता है। करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहरों में अस्थायी या असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर

रहे हैं। शहरी अर्थव्यवस्था इन श्रमिकों पर निर्भर है, फिर भी सामाजिक व्यवहार में वे अक्सर अदृश्य रहते हैं। हम उनके श्रम का लाभ उठाते हैं, पर उनके आवास, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर उदासीन बने रहते हैं। यह उदासीनता सहानुभूति की सीमा को दर्शाती है, जहां समस्या को देखा तो जाता है, पर उस अपना नहीं माना जाता।

डिजिटल युग ने संवेदनओं को भी एक नए रूप में ढाल दिया है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे से जुड़े आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। यह तथाकथित डिजिटल सहानुभूति हमें प्रतिक्रिया तो देती है, पर सहभागिता नहीं सिखाती। असल में केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति

रहे हैं। शहरी अर्थव्यवस्था इन श्रमिकों पर निर्भर है, फिर भी सामाजिक व्यवहार में वे अक्सर अदृश्य रहते हैं। हम उनके श्रम का लाभ उठाते हैं, पर उनके आवास, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर उदासीन बने रहते हैं। यह उदासीनता सहानुभूति की सीमा को दर्शाती है, जहां समस्या को देखा तो जाता है, पर उस अपना नहीं माना जाता।

डिजिटल युग ने संवेदनओं को भी एक नए रूप में ढाल दिया है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे से जुड़े आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। यह तथाकथित डिजिटल सहानुभूति हमें प्रतिक्रिया तो देती है, पर सहभागिता नहीं सिखाती। असल में केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति

रहे हैं। शहरी अर्थव्यवस्था इन श्रमिकों पर निर्भर है, फिर भी सामाजिक व्यवहार में वे अक्सर अदृश्य रहते हैं। हम उनके श्रम का लाभ उठाते हैं, पर उनके आवास, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर उदासीन बने रहते हैं। यह उदासीनता सहानुभूति की सीमा को दर्शाती है, जहां समस्या को देखा तो जाता है, पर उस अपना नहीं माना जाता।

डिजिटल युग ने संवेदनओं को भी एक नए रूप में ढाल दिया है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे से जुड़े आंकड़े, तस्वीरें और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। यह तथाकथित डिजिटल सहानुभूति हमें प्रतिक्रिया तो देती है, पर सहभागिता नहीं सिखाती। असल में केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति



दोनों दलों के डेढ़ दर्जन प्रत्याशियों का टिकट कटने के बाद मैदान में सीधा युति से टकराव

भिवंडी मनपा चुनाव में भाजपा व शिवसेना (शिंदे) के बागी बिगड़ रहे महायुति का खेल

दोनों दलों के कई पूर्व नगरसेवकों की पत्नी,बेटे व कई पदाधिकारियों ने बढ़ाई पार्टियों की चिंता

भिवंडी (संवाददाता)

► मंत्र न्यूज

भिवंडी मनपा चुनाव में भाजपा व शिवसेना(शिंदे)के कई बागी प्रत्याशी,निर्दलीय व अन्य पार्टियों के टिकट पर चुनाव मैदान ने उत्तरकर महायुति का खेल बिगाड़ रहे हैं।दोनों दलों के डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी महायुति के प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बन गए हैं।आलम यह है कि दोनों दलों के कई प्रत्याशियों के बेटे, पत्नी एक दूसरे पार्टियों के पैनल के विरुद्ध अन्य पार्टियों व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।जिससे महायुति की चिंता बढ़ गई है।

भिवंडी मनपा के 90 सीटों के लिए 439 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।जिसमें से भाजपा व शिवसेना(शिंदे) के डेढ़ दर्जन से ज्यादा

प्रत्याशी टिकट कटने के कारण हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में महायुति को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।सस्से हैरत की बात यह है कि भाजपा के कई पैनल के सामने शिवसेना (शिंदे)के प्रत्याशी के पुत्र व पत्नी चुनाव मैदान में हैं।वही भाजपा पैनल के सामने शिवसेना(शिंदे) के प्रत्याशी के टक्कर दे रहे हैं।प्रभाग क्रमांग 16 क में पूर्व भाजपा नगरसेविका कल्याणप पदमा भूमेश का टिकट पार्टी द्वारा काटे जाने के बाद वह इसी प्रभाग में सपा की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं।जबकि प्रभाग 16 ब में भाजपा की महिला महासचिव डिपल व्यास निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं।इसी तरह 17 क में भाजपा के पूर्व नगरसेवक मुरली मच्छा व वासम अरुण राजेंद्र निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 22 में भाजपा उम्मीदवार चुनाव लड़ने के कारण भाजपा के महासचिव राजू गाजेंगी की पत्नी लता गाजेंगी,भाजपा की पूर्व नगरसेविका

दीपाली दिनेश पाटिल व भाजपा उत्तरभारतीय मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह की बेटी स्नेहा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर भाजपा व शिवसेना(शिंदे) महायुति का टेंशन बढ़ा दिया है।इसी तरह से प्रभाग क्रमांक 21 में शिवसेना (शिंदे) के पैनल के सामने भाजपा के प्रभाग क्रमांक 23 के उम्मीदवार निलेश चौधरी की पत्नी दक्षता चौधरी, टिकट न मिलने से भाजपा से नाराज श्याम भोईर व पूर्व नगरसेवक साईनाथ पवार के पुत्र विराज पवार व सिद्धि पाटिल जयहंद सेना की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं।वही प्रभाग क्रमांक 23 में भाजपा के पैनल के सामने शिवसेना(शिंदे) के प्रभाग क्रमांक 22 के उम्मीदवार मनोज काटेकर के पुत्र तेजस काटेकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पैनल लता गाजेंगी,भाजपा की पूर्व नगरसेविका

रहे हैं।बागियों का कहना है कि जिस प्रभाग से वे भाजपा व शिवसेना(शिंदे) से टिकट मांग रहे थे, टिकट नकारे जाने के बाद अब वे उसी प्रभाग से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं।टिकट कटवाने में अहम भूमिका निभाने वालों को हराना ही उनका मकसद हैं।जिनके सामने महायुति लाचार भाजपा के प्रभाग क्रमांक 23 के उम्मीदवार भुगतना पड़ सकता है।बता दे कि भिवंडी में हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों के 30 सीट पर भाजपा, जबकि 20 सीट पर शिवसेना महायुति चुनाव मैदान में है।जिसमें से भाजपा के छह प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं इसके बाद अब अन्य सीटों पर बागियों द्वारा टक्कर दिए जाने से न सिर्फ मुकाबला दिलचस्प हो गया है, बल्कि महायुति में आपसी खींचतान को लेकर खलबली मची हुई है।

रात में 2 देशी पिस्टल व 3 कारतूस बरामद, तीन गिरफ्तार

भिवंडी।भिवंडी मनपा चुनाव की सरगर्मी के बीच शहर में अवैध हथियारों की लगातार बरामदगी ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की अलग-अलग कार्रवाई में पिछले दो दिन में दो देशी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि मनपा चुनाव नजदीक आते ही शहर में रोजाना हथियारों की बरामदगी सामने आ रही है, जिससे चुनावी माहौल में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

पहली कार्रवाई शांतिनगर पुलिस थाने की ओर से की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि टेम्पर इलाके में कुछ संदिग्ध युवक हथियार लेकर घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर 3 जनवरी की रात करीब 9.30 बजे पुलिस ने छापेमारी कर आकाश कुमार बनराज

भारतीय (20) और राजेश बनराज भारतीय (21) को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 20 हजार रुपये कीमत की स्टील बांडी की देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मूल निवासी बताए जा रहे हैं और फिलहाल भिवंडी में रह रहे थे।

दूसरी कार्रवाई कोनगांव पुलिस थाने की ओर से की गई। 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे अस्मिता कंपाउंड, खाड़ी इलाके में पुलिस ने नासिर अंसार शेख (23) को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 16 हजार रुपये कीमत की लोहे की देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर घूम रहा था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन सकता

था।

दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भारतीय हथियार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार उन्हें कहाँ से मिले और इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। मनपा चुनाव को देखते हुए लगातार हो रही हथियारों की बरामदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस विभाग के सुत्रो का कहना है कि चुनाव के मद्देनज़र शहर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई है तथा आने वाले दिनों में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जा सकें।

भिवंडी सब जेल में कैदी का तांडव, सरकारी काम में बाधा, CCTV व लाइटें तोड़ीं

भिवंडी। भिवंडी स्थित सब जेल में एक कैदी द्वारा जमकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। आरोपी कैदी ने जेल परिसर में न केवल उत्पात मचाया, बल्कि शासकीय इ्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को धमकाने, गाली-गलौज करने और सरकारी कार्यों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। इस घटना से कुछ देर के लिए जेल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मामले में शांतिनगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 4 फरवरी की सुबह करीब 10.30 बजे भिवंडी सब जेल में घटी। शिकायतकर्ता पुलिस हवलदार सचिन कृष्णा जगताप, जो

शांतिनगर पुलिस थाने में तैनात हैं, उस समय शासकीय कर्तव्य का पालन कर रहे थे। इसी दौरान फैयाज इस्लाम शेख (25), जो मुंबई का निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में सब जेल में बंद है, अचानक आक्रामक हो गया। आरोप है कि कैदी ने जेल प्रशासन और पुलिसकर्मियों पर चिल्लाते हुए कहा कि उसके ऊपर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, ‘मुझे छोड़ दो, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे ऊपर कई केस हैं’। इसके बाद आरोपी ने जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खींचकर नीचे पटक दिया, जिससे कैमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही उसने तीन बल्ब तोड़ दिए और जेल की अन्य संपत्ति को भी

नुकसान पहुंचाया। जब पुलिस हवलदार और अन्य जेल स्टाफ ने उसे शांत कराने और समझाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने जानबूझकर सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों को डराने-धमकाने का प्रयास किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए शांतिनगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के इस व्यवहार से जेल की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन भंग हुआ है। मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन देसाई द्वारा की जा रही है।

भिवंडी (संवाददाता)

► मंत्र न्यूज

भिवंडी- निजामपुर शहर महानगरपालिका चुनाव में उत्तर भारतीय समाज की उपेक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पालिका क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत मतदाता उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और गांवों से आए नागरिकों के हैं, जो वर्षों से कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी को मतदान करते आ रहे हैं। इसके बावजूद टिकट वितरण में इस समाज को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। चुनाव के दौरान रैलियों, प्रचार और जनसंपर्क में सक्रिय भूमिका निभाने वाले उत्तर भारतीय

मतदाताओं का कहना है कि उन्हें केवल भोड़ जुटाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने तक सीमित रखा जाता है। सम्मान और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी की अपेक्षा के बावजूद हर चुनाव में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। चुनावी उम्मीदवार के आंकड़ों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी ने प्रभाग 3 (क) से संतोष कुमार राय को प्रत्याशी बनाया है। राकांपा (अजीत पवार गुट) ने प्रभाग 8 (ड) से अर्जुन महेन्द्र गुप्ता तथा प्रभाग 11 (ड) से अजय राजेन्द्र श्रीवास्तव को टिकट दिया है। कांग्रेस ने प्रभाग 20 (ड) से जितेन्द्र हरिनाथ पाल को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने प्रभाग 16 (ब) से ठाकुर क्षमा मनोज को प्रत्याशी बनाया है।

सुदर्शन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 185 बच्चों का हुआ स्वर्णप्राशन - डॉ जी एस तोमर

प्रयागराज।सुदर्शन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर त्रिवेणीपुरम, झूँसी एवं विश्व आयुर्वेद मिशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वर्णप्राशन शिविर का आयोजन झंडु इमामी समूह के सौजन्य से दि. 5 जनवरी, 2026 को पुष्य नक्षत्र के अवसर पर किया गया जिसमें नवजात शिशु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के 185 बच्चों को स्वर्ण विन्दु के रूप में स्वर्णप्राशन की खुराक दी गयी। विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष, प्रो. (डॉ) जी एस तोमर ने स्वर्ण बिंदु के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि स्वर्णप्राशन से बच्चों को दीर्घायु, ऊर्जा, मेधाशक्ति व रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ बाल्यावस्था में होने वाले सामान्य रोगों से भी लड़ने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। डॉ तोमर ने बताया कि विगत तीन वर्षों से अधिक समय से स्वर्णप्राशन



का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है । सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर इनमें से 75 प्रतिशत बच्चे निरन्तर इसका लाभ ले रहे हैं। प्रत्येक माह 25 प्रतिशत नए बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं । पूछे जाने पर अधिकांश अभिभावकों का अभिमत है कि उनके बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है तथा बार बार होने वाली मौसमी बीमारियों से भी उनका बचाव हो रहा है । सुदर्शन आयुर्वेद केन्द्र के निदेशक राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि स्वर्ण प्राशन की यह खुराक विगत 3 वर्षों से प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों को निःशुल्क वृद्धि में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है । इस पुनीत संस्कार हेतु वांछित औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु डॉ तोमर ने झंडु इमामी समूह का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन किया ।

भिवंडी (संवाददाता)

► मंत्र न्यूज

भिवंडी मनपा चुनाव में इ्यूटी पर लगे मनपा कर्मचारियों को दूसरे प्रशिक्षण शिविर में हाजिर रहना अनिवार्य है जो भी कर्मचारी इसमें गैरहाजिर रहेगा,उस पर मुकदमा किया जाएगा।इस प्रकार की चेतावनी मनपा आयुक्त अनमोल सागर ने दी है।

मालूम भिवंडी मनपा का चुनाव आगामी 15 जनवरी को होने वाला है।जिसके लिए चुनाव आयोग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई। चुनाव में बड़े पैमाने पर मनपा अधिकारियों व कर्मचारियों को इ्यूटी पर लगाया गया है।जिनके लिए दूसरा चुनाव प्रशिक्षण का आयोजन 6 व 7 जनवरी को रखी गई है। यह ट्रेनिंग कर्मचारियों के लिए

बहुत जरूरी है और सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग में शामिल होना जरूरी है।क्योंकि पिछले प्रशिक्षण में मनपा के कई कर्मचारी अनुपस्थित रहे थे।जिसके मद्देनजर आयुक्त अनमोल सागर इ्यूटी में लगाए गए सभी मनपा कर्मचारियों को इस प्रशिक्षण में उपस्थित रहा अनिवार्य कर दिया है।उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी कर्मचारी इस प्रशिक्षण में अनुपस्थित नहीं रहेगा।चुनाव

अधिकारी व आयुक्त अनमोल सागर ने संबंधित कर्मचारी विभागों को आदेश दिया है कि जो कर्मचारी ट्रेनिंग में शामिल नहीं होंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज करें और इसे उनकी सर्विस बुक में दर्ज करें।जिससे लेकर मनपा में हड़कंप मच गया है।सूत्र बताते हैं कि चुनावी इ्यूटी में लगाए गए कई कर्मचारी इसमें से अपना नाम निकलने के लिए सेटिंग में लगे हैं।

यूपी पुलिस भर्ती में योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान

लखनऊ (एजेंसी)। प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध

तथा बैडमिंटन युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि अनुशासन उनका स्वभाव है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2013 में महाप्रबंधक पुरस्कार तथा वर्ष 2024 में विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2025 के महाकुंभ के दौरान रेलवे प्रबंधन को सुचारु सुरक्षित और ऐतिहासिक बनाने में उनकी बेमोलरु स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान से प्रबंधन में स्नाकोत्तर शिक्षा पूर्ण की। इन सभी अनुभवों ने उन्हें आधुनिक रेल प्रस्तेान का पूर्ण और सक्षम अधिकारी बनाया। शारीरिक दक्षता और अनुशासन में भी वे अग्रणी हैं। तैराकी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन में दक्ष श्री शुक्ल ने उत्तर भारत

समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।

हम आपको यह भी बता दें कि साल 2025 के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं को 2026 का बड़ा तोहफा देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोब्रति बोर्ड द्वारा जारी इस अधिसूचना ने साफ संकेत दिया था कि योगी सरकार में रोजगार केवल घोषणा नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन चुका है। वहीं बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को बोर्ड विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। देखा जाये तो योगी सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझती है और

गोरखपुर/बस्ती। जब प्रतिभा, परिश्रम और राष्ट्रसेवा एक साथ चलते हैं, तब इतिहास बनता है। भारतीय रेल के कर्मट और दूरदर्शी अधिकारी श्री कृष्ण शुक्ल को उनके असाधारण, निर्णायक और परिवर्तनकारी योगदान के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में वे मुख्य माल परिवहन प्रबंधक, पूर्वांचल रेलवे, गोरखपुर के पद पर कार्यरत हैं। जनपद बस्ती के ग्राम सेवरा (लाला छावनी) से निकलकर देश की रेल व्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने तक की उनकी यात्रा संघर्ष, संकल्प और सफलता की अनुपम मिसाल है। गाँव के प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा आरंभ कर उन्होंने छावनी स्थित अशोक इंटर कॉलेज से माध्यमिक तथा सुल्तानपुर के वलीपुर स्थित पी पी इंटर कॉलेज से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी यह यात्रा सिद्ध करती है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। शैक्षणिक क्षेत्र में श्री शुक्ल ने लखनऊ विश्वविद्यालय में असाधारण उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। उन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं, गणित समूह में स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तीन स्वर्ण पदक अर्जित किए। ये उपलब्धियाँ उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और अकादमिक उत्कृष्टता का प्रमाण हैं।

विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उन्होंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कनिष्ठ अनुसंधानवृत्ति परीक्षा तीन बार उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर नया मानक स्थापित किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अनुसंधानवृत्ति के अंतर्गत पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से आमंत्रण भी प्राप्त हुआ, किंतु उसी समय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन होने पर उन्होंने अनुसंधान के स्थान पर प्रत्यक्ष राष्ट्रसेवा को प्राथमिकता दी और भारतीय रेल यातायात सेवा में प्रवेश किया। रेलवे सेवा में उनका कार्यकाल परिणामोन्मुख और प्रभावशाली निर्णयों के लिए जाना जाता है। टुंडला में मंडल यातायात प्रबंधक, आगरा में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी, झांसी और

दिग्गज ऑलराउंडर ने भारत की अगली कप्तान की भविष्यवाणी की

मंधाना की जगह जोमिमा रोड्रिग्स पर दिखाया भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की ऐतिहासिक महिला विश्व कप 2025 टीम के बाद अब चर्चा का केंद्र टीम का भविष्य और नेतृत्व है। मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर 36 वर्ष की हो चुकी हैं और उनके शानदार करियर के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उत्तराधिकारी की खोज तेज हो गई है। जहां स्मृति मंधाना को लंबे समय से अगला कप्तान माना जा रहा था, वहीं दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज ऑलराउंडर मैरिज़ेन कैप ने एक अलग नाम आगे बढ़ाकर बहस को नया मोड़ दे दिया है। उनका मानना है कि भारत को ऐसा लीडर चाहिए जो टीम को जोड़कर रख सके।

विश्व कप जीत के बाद भारतीय महिला टीम स्थिरता और निरंतरता

के दौर में है, लेकिन कप्तानी का सवाल अब टाला नहीं जा सकता। हरमनप्रीत ने कई सालों तक टीम का नेतृत्व किया है, पर उम्र और भविष्य की योजना को देखते हुए बीसीसीआई को दीर्घकालिक विकल्प की ज़रूरत है। ऐसे में लीडरशिप सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को साथ लेकर



चलने की क्षमता भी अहम बन गई है।

5 जनवरी 2026 को दिए एक इंटरव्यू में मैरिज़ेन कैप ने जेमिमा रोड्रिग्स को भारत की अगली कप्तान के रूप में देखने की इच्छा जताई। कैप के अनुसार, जेमिमा में वर्षों से लीडरशिप के गुण दिखाई देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कप्तानी केवल

फील्ड सेटिंग और फैसलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि टीम के भीतर विश्वास और एकता बनाना भी उनका ही ज़रूरी है-और जेमिमा इसमें स्वाभाविक रूप से आगे हैं। कैप ने जोर देकर कहा कि जेमिमा की सबसे बड़ी ताकत उनकी पर्सनैलिटी है। वह खिलाड़ियों को जोड़ती हैं, माहौल को सकारात्मक रखती हैं और हर खिलाड़ी की परवाह करती हैं। हाल ही में विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई उनकी नाबाद 127 रनों की पारी ने यह भी साबित किया कि वह बड़े मंच और दबाव को संभाल सकती हैं। 25 साल की उम्र में इस तरह की परिपक्वता उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार बनाती है।

बीते वित्त वर्ष 49 क्रिंटो करेंसी एक्सचेंज एफआईयू के पास पंजीकृत : रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 49 क्रिंटो करेंसी एक्सचेंज वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के पास पंजीकृत हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से ज्यादातर भारत में स्थित हैं। यह पंजीकरण इस क्षेत्र से धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए देश की कानूनी व्यवस्था के तहत किया गया है। इन एक्सचेंजों द्वारा संपीय एजेंसी को दी गई संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के विश्लेषण में पाया गया कि क्रिंटो फंड का दुरुपयोग हवाला, जुआ, घोटाले, धोखाधड़ी और अवैध

वयस्क सामग्री वाली वेबसाइट चलाने जैसी गंभीर अपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।

कानूनी भाषा में क्रिंटो करेंसी को आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (वीडीए) कहा जाता है और इनमें व्यापार करने वाले एक्सचेंजों को वीडिए सेवा प्रदाता (वीडीए एसपी) कहा जाता है। इन एक्सचेंजों को 2023 में भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत लाया गया था। पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग संस्था होने के नाते, इन एक्सचेंजों को एफआईयू को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट सौंपनी होती है।



सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाना सामाजिक आर्थिक नजरिये से ज़रूरी : स्मृति ईरानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाना सामाजिक के साथ आर्थिक नजरिये से भी ज़रूरी है। ईरानी ने यहां आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 को संबोधित करते हुए कहा, महिलाओं को सफलता के शिखर पर भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महिलाएं अब बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय का दायित्व संभाल चुकीं ईरानी ने स्पार्क पहल का उल्लेख भी किया जिसका उद्देश्य 300 शहरों में एक लाख महिला उद्यमियों को ऋण, औपचारिकता और संस्थागत सहयोग तक पहुंच उपलब्ध कराना है।

सम्मेलन के दूसरे दिन एक अभियान की शुरुआत भी हुई, जिसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आर्थिक वृद्धि और रोजगार के प्रमुख चालक के रूप में मजबूत

करना है। टाई के मुताबिक, यह पहल अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियां और 100 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए सरकारों, उद्योग संगठनों, पूंजी प्रदाताओं और विश्वभर के टाई चैंप्टर को जोड़ा जाएगा।

मुख्य फोकस क्षेत्रों में नियामकीय सरलीकरण, पूंजी तक पहुंच, कौशल विकास, तकनीक अपनाना और क्लस्टर-आधारित क्षेत्रीय विकास शामिल हैं। एमएसएमई पर केंद्रित एक अन्य सत्र में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने स्थिर नियमों, आसान जीएसटी अनुपालन, बेहतर ऋण उपलब्धता और प्रौद्योगिकी-आधारित क्लस्टर विकास की भूमिका पर चर्चा की। सत्र के बाद आंध्र प्रदेश सरकार, टाई हैदराबाद और टाई विशाखापत्तनम के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। इससे पहले भविष्य के शहरों के निर्माण पर केंद्रित सत्र में वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी पर चर्चा हुई।

भारत का यूरिया आयात अप्रैल-नवंबर में दोगुने से अधिक होकर 71.7 लाख टन हो गया : एफएआई

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू उत्पादन में गिरावट से चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीने में भारत का यूरिया आयात दोगुने से अधिक होकर 71.7 लाख टन हो गया है जो किसानों की मांग को पूरा करने के लिए विदेशी आपूर्ति पर देश की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2024-25 के दौरान यूरिया का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 32.6 लाख टन की तुलना में 120.3 प्रतिशत बढ़कर 71.7 लाख टन हो गया। आंकड़ों के अनुसार, घरेलू यूरिया उत्पादन अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के बीच 3.7 प्रतिशत घटकर 1.97 करोड़ टन रहा। कुल यूरिया बिक्री 2.3 प्रतिशत बढ़कर 2.54 करोड़ टन तक पहुंच गई। एफएआई के चेयरमैन एस. शंकर सुक्रमय्यम ने एक बयान में कहा,

‘‘हालांकि हमने समन्वित योजना के माध्यम से बिक्री में वृद्धि हासिल की है लेकिन आयात पर महत्वपूर्ण निर्भरता (विशेष रूप से यूरिया और डीएपी के लिए) रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के महत्व को दर्शाती है।’’ यूरिया का आयात नवंबर माह में 68.4 प्रतिशत बढ़कर 13.1 करोड़ टन हो गया, जबकि नवंबर 2024 में यह 7.8 लाख टन था। यूरिया की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में नवंबर माह में 4.8 प्रतिशत बढ़कर 37.5 लाख टन हो गई। अन्य



महत्वपूर्ण मृदा पोषक तत्व, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आयात पर निर्भरता भी बढ़ रही है। डीएपी का आयात अब कुल आपूर्ति का 67 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष 56 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-नवंबर के दौरान इसकी बिक्री 71.2 लाख टन पर स्थिर रही। घरेलू डीएपी उत्पादन में 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 26.8 लाख टन रह गया। एफएआई के महानिदेशक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि इन आंकड़ों में

विजय हजारे ट्रॉफी 2026 वापसी की चर्चा के बीच विराट कोहली दिल्ली के लिए नहीं खेलेंगे अगला मैच

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली रेलवे के खिलाफ होने वाला विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का मैच नहीं खेलेंगे। दोनों राज्य एसोसिएशन बीसीसीआई के प्रमुख 50 ओवर के टूर्नामेंट के पांचवें राउंड में 6 जनवरी को आमने-सामने होने वाले थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विराट केएससीए क्रिकेट ग्राउंड पर रेलवे के खिलाफ दिल्ली के विजय हजारे ट्रॉफी मैच के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। रिपोर्ट में विराट की गैरमौजूदगी का कारण नहीं बताया गया है।

ख़ास बात यह है कि इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने दिल्ली के लिए पहले दो मैच खेले और एक शतक

भारतीय स्टार 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में सीधे न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्शन में दिखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 से पहले बोर्ड ने भारत के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को निर्देश दिया था कि अगर उन्हें वनडे के लिए टीम में बने रहना है



तो उन्हें कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने होंगे। इसलिए रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और सभी बड़े खिलाड़ियों ने इस दिसंबर विंडो में अपने राज्य एसोसिएशन की जर्सी पहनी। दिल्ली के लिए विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच खेला और शानदार 131 (101) रन बनाए जिसमें 14 चौकें और तीन छक्के शामिल थे। इसके बाद उन्होंने गुजरात का सामना किया और 77 (61) रन बनाए। अगर विराट अब आने वाला विजय हजारे ट्रॉफी मैच नहीं भी खेलते हैं, तो बीसीसीआई की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही उनकी बात मान ली है।

भारत-इजराइल व्यापार को रुपए में करने को बढ़ावा देगा एसबीआई

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों में गहराई लाने और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर जारी चर्चाओं के बीच इजराइल में उपस्थित एकमात्र भारतीय ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) रुपए में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा है। एसबीआई इजराइल के मुख्य कार्यालयक अधिकारी (सीईओ) वी. मणिवन्नन ने कहा, ‘‘भारत के सहयोगी देशों से होने वाले महत्वपूर्ण व्यापार एवं वैश्विक व्यापार समुदाय में भारतीय रुपए में व्यापार करने की बढ़ती रुचि को देखते हुए, हमारे बैंकिंग नियामक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के निर्यात एवं आयात का निपटारा भारतीय रुपए में करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत

इजराइल को भागीदार देशों में से एक के रूप में चुना गया है।’’

एसबीआई के अधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से निर्यात/आयात करने वाली इजराइली संस्थाएं भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त करेंगी और देंगी जिसे इजराइली विक्रेता/खरीदार से माल या सेवाओं की आपूर्ति/ खरीद के ‘इनवॉइस’ के बदले विशेष रुपी वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) में जमा किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘एसबीआई तेल अवीव के पास इन लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां मौजूद हैं।’’ एसबीआई की शाखा

ने हाल ही में इजराइल-भारत वाणिज्य चैंबर के सहयोग से रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई बैठकें एवं वेबिनार आयोजित किए। इन चर्चाओं में इजराइल की अधिकतर प्रमुख रक्षा संस्थाओं के अधिकारी शामिल हुए थे। हाल ही में 40, 000 से अधिक भारतीय कामगारों के इजराइल कार्यबल में शामिल होने के साथ एसबीआई, तेल अवीव शाखा में भारत में उनके अनिवसी प्रवासी खाते खोलने की सुविधा प्रदान करके भारत में प्रेषण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने की भी कोशिश कर रहा है। एसबीआई ने 2007 में इजराइल में अपनी शाखा खोली और तब से एक पूर्ण विकसित परिचालन बनाए रखने में सफल रहा है। यह वैश्विक महामारी तथा क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण दो वर्ष से अधिक समय तक चली उथल-पुथल के बावजूद इसकी दृढ़ता को दर्शाता है।



रोजगार संकट से निपटने के लिए उद्योग जगत की बड़ी पहल, 10 करोड़ जॉब्स का प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में रोजगार की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों ने सोमवार को ‘हैट्रेड मिलियन जॉब्स’ नाम से एक बड़ी राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की। इस मिशन का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत में 10 करोड़ नए रोजगार अवसर पैदा करना है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब देश तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद पर्याप्त रोजगार सृजन की समस्या से जूझ रहा है।

इस पहल की घोषणा सॉफ्टवेयर उद्योग संगठन नैसकॉम के सह-संस्थापक हरीश मेहता, वैश्विक उधमी नेटवर्क द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के संस्थापक ए. जे. पटेल और सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी के संस्थापक यतीश राजावत ने संयुक्त रूप से की।

संस्थापकों के मुताबिक, भारत में कार्यशील आयु की आबादी हर साल लगभग 1.2 करोड़ की दर से बढ़ रही है, जबकि विनिर्माण जैसे पारंपरिक रोजगार क्षेत्र

अपेक्षित गति से विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में देश को अपने जनसांख्यिकीय लाभों का पूरा फायदा उठाने के लिए हर साल 80 से 90 लाख नई नौकरियां सृजित करने की ज़रूरत है।

हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन रोजगार की रफ्तार उत्पादन और आर्थिक विस्तार के मुकाबले पीछे रही है। स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से कई क्षेत्रों में शुरुआती स्तर की नौकरियां कम हो रही हैं, जिससे यह आशंका गहराने लगी है कि आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के बीच दूरी बढ़ सकती है। हैट्रेड मिलियन जॉब्स मिशन के तहत उद्यमिता, कौशल विकास और श्रम-प्रधान उद्योगों को भारत की रोजगार नीति के केंद्र में रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार सृजन को आर्थिक प्रगति का प्रमुख पैमाना बनाना है।

विनीत कुमार सिंह और सैयामी खेर ने अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग शुरू की

अभिनेता विनीत कुमार सिंह ने नई एनर्जी और एक्साइटिंग प्लान्स के साथ नए साल की शुरुआत की है। 2025 में लगातार हिट फिल्मों, जिसमें उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक ‘छावा’ भी शामिल है, के बाद, 2026 विनीत के लिए जोरदार तरीके से शुरू हो रहा है। एक्टर ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइनर से डायरेक्टर बने विक्रम फडनिस के साथ हाथ मिलाया है। विनीत ने कहानी को ‘खूबसूरत’ और अपने दिल के करीब बताया है, हालांकि अभी डिटेल्स को सीक्रेट रखा गया है।

विनीत कुमार सिंह और सैयामी खेर ने अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। सिंह ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की। इस पोस्ट में पूजा समारोह की तस्वीरों और वीडियो के साथ फिल्म के ‘क्लेपर बोर्ड’



गया है। इसमें ताहिर राज भसीन भी काम कर रहे हैं। सैयामी खेर जल्द ही अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ फिल्म हैवान में दिखाई देंगी। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रिया पिलगांवकर भी हैं। विनीत कुमार सिंह हाल ही में फिल्म तेरे इश्क

में नजर आए थे। नवंबर में रिलीज हुई इस फिल्म में कृति सैनन और धनुष मुख्य भूमिकाओं में थे और इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया था। फिल्म में सिंह ने वी शेखवत का किरदार निभाया था।

युवा के राउंडटेबल शो बी एमैन, यार’ में, विनीत कुमार सिंह ने अपने शुरुआती करियर के मुश्किल दौर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि, अपने स्ट्रगल के दिनों में, इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उन्हें कई छोटी और अजीब नौकरियां करनी पड़ीं। विनीत ने बताया कि उन्होंने सुनील शेट्टी के बॉडी डबल के तौर पर भी काम किया और बैकग्राउंड रोल किए जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं खींचते थे। उनके लिए, वे अनुभव उनकी यात्रा का हिस्सा थे और उन्होंने उन्हें अपने सपने से जुड़े रहने में मदद की। उन्होंने समझाया कि ऐसे समय में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अंदर से मज़बूत रहें और हार न मानें।

जागरण में बेकाबू हुई सुधा चंद्रन, भजन गाया फिर जोर-जोर से हंसने लगीं, क्या माता चढ़ी?

नागिन में हाल ही में नज़र आई एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक नया क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस क्लिप में, अनुभवी एक्ट्रेस भजन में शामिल होते समय एक अजीब सी हालत में दिखीं। जब भजन में मौजूद कई दूसरे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उन्हें काट भी लिया। दूसरे भक्तों ने बताया कि भक्ति के उस पल में ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी आत्मा का साया है।

सुधा हॉल में इधर-उधर कूदती हुई दिखीं, वह अपने इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने लाल और सफेद साड़ी पहनी थी, साथ ही माथे पर एक हेडबैंड बांधा हुआ था जिस पर ‘जय माता दी’ लिखा था। जैसे-जैसे भजन चलता रहा, एक्ट्रेस इमोशनली अबुत ज्यादा भावुक हो गईं और अपने हाव-

भाव पर कंट्रोल खो बैठीं। एक समय पर, दूसरे लोग उन्हें पकड़ने और उन्हें कंट्रोल में लाने में मदद करने के लिए आगे आए। सुधा एक ऐसे आदमी के हाथ काटती हुई दिखीं जिसने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। एक समय पर, तीन लोग उन्हें पकड़े और सहारा देते हुए दिखाते हैं ताकि वह गिरें नहीं या खुद को चोट न पहुंचा लें। माना जा रहा

है कि यह फुटेज एक धार्मिक कार्यक्रम का है जहां सुधा चंद्रन माता के भजन में हिस्सा ले रही थीं। जैसे-जैसे भक्ति गीत तेज़ होते हैं, उनके हाव-भाव और ज़्यादा साफ होने लगते हैं, जिससे उनके आस-पास के लोग उन्हें संभालने के लिए आगे आते हैं। इस वीडियो पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई लोगों ने इस पल को पूजा



के दौरान एक गहरी आध्यात्मिक समाधि बताया है। सुधा को नागिन फ्रैंचाइज़ी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी अटेंशन मिला, जहाँ उन्होंने पहले दो सीज़न में चालाक माँ यामिनी रहेजा का किरदार निभाया था। उन्होंने ये हैं मोहब्बतें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और माता की चौकी, कलकत्ता में भक्ति की शक्ति जैसे टीवी शो में भी काम किया है। पिछले कुछ सालों में, उन्होंने फिल्मों में दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस किया है और काहीं किसी रोज़, नागिन 6, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे पॉपुलर शो के ज़रिए टेलीविज़न पर घर-घर में मशहूर हो गईं। दशकों लंबे करियर के साथ, सुधा चंद्रन अपनी प्रतिभा, ताकत और दशकों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए - स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह - तारीफ बटोर रही हैं।

चुनावी महासफर

वार्ड 39: जनता का भरोसा, शिवसेना की विनया सावंत ने मैदान संभाला

दिव्यांश

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका चुनाव 2026 में वार्ड 39 में राजनीतिक माहौल गरम है। इस बार शिवसेना (शिंदे गुट) ने विनया विष्णु सावंत को वार्ड की जनता की सेवा और विकास के लिए मैदान में उतारा है।

विनया सावंत ने पिछले वर्षों में वार्ड 39 के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों से सड़क, पानी, सीवर और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों में सुधार हुआ है। स्थानीय महिलाओं और युवाओं की समस्याओं के समाधान में उनका योगदान भी हमेशा सराहा गया है।

शिवसेना के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जनता विकास और भरोसे के आधार पर अपना निर्णय ले रही है। पार्टी का दावा है कि विनया सावंत की लोकप्रियता और सशक्त नेतृत्व वार्ड 39 में जीत की संभावनाओं को



मजबूत करता है। विनया सावंत ने कहा: 'मेरा मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि वार्ड 39 के हर नागरिक के लिए ठोस और स्थायी विकास करना है। जनता के भरोसे पर खरा उतरना मेरी पहली प्राथमिकता है।' वार्ड 39 में प्रचार अभियान जोरों पर है। स्थानीय नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता मिलकर जनसंपर्क, मोहल्ला बैठक और सड़क सभा के माध्यम से जनता से जुड़े हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि वार्ड 39 में यह चुनाव विकास की राजनीति बनाम राजनीतिक विरोध का समर्थन कर रही है जो साफ़ नीयत और ठोस काम करता हो। वार्ड की जनता के लिए यह चुनाव केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि अपने वार्ड के विकास और भरोसे की लड़ाई है।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका चुनाव से ठीक पहले शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा भाजपा नेता अमित साठम के नाम को लेकर की गई टिप्पणी न केवल अमर्यादित है, बल्कि यह मराठी अस्मिता और लोकतांत्रिक राजनीति पर सीधा हमला है। किसी जनप्रतिनिधि के नाम का उपहास करना राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि मुद्दों से पलायन और वैचारिक दिवालियापन का प्रमाण है। प्रो. दयानंद तिवारी ने कई शब्दों में कहा कि यह टिप्पणी किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले करोड़ों मराठी, कोकणी और मालवणी समाज के स्वाभिमानी नागरिकों का अपमान है। यह वही समाज है जो परिश्रम, संघर्ष केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि अपने वार्ड के विकास और भरोसे की लड़ाई है।



प्रोफ़ेसर डॉ दयानंद तिवारी
प्रवक्ता भाजपा,
मुंबई, महाराष्ट्र

उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में अवैध गतिविधियों, जनसंख्या असंतुलन और तथाकथित 'मोमेडीयनाइजेशन' जैसे गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर सवाल उठाए, तब शिवसेना (यूबीटी) नेतृत्व तथात्मक जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों और भाषाई कटाक्ष पर उतर आया। यह साफ संकेत

है कि उनके पास न तो ठोस उत्तर हैं और न ही अपने लंबे कार्यकाल की कोई ठोस उपलब्धि। प्रो. तिवारी ने बीएमसी के बजट और कथित 'तीन लाख करोड़ रुपये के घोटाले' के मुद्दे पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि दशकों तक बृहन्मुंबई महानगरपालिका पर शासन करने वाली पार्टी यदि आज भ्रष्टाचार का रोना रो रही है, तो यह उनके ही कुप्रबंधन और विफलताओं की मौन स्वीकारोक्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई का चुनाव नामों के मज़ाक, भावनात्मक उकसावे और भाषाई अपमान का नहीं है, बल्कि विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और मराठी समाज के सम्मान का चुनाव है।

भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज के आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। प्रो. दयानंद तिवारी ने विश्वास जताया कि मुंबई की जागरूक जनता अब अहंकार और वंशवाद की राजनीति को नकार कर काम, ईमानदारी और मुद्दों पर आधारित राजनीति को चुनेगी – और यही इस चुनाव में निर्णायक बदलाव की शुरुआत होगी।

वार्ड नम्बर 37

जनता का भरोसा बना ताकत, निर्दलीय सुचित्रा नाइक को बढ़त

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका चुनाव में वार्ड नम्बर 37 इस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी सुचित्रा नाइक ने पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए चुनावी मैदान में जबरदस्त बढ़त बनाती दिख रही हैं। जनसमर्थन की यह लहर साफ संकेत दे रही है कि मतदाता इस बार पार्टी नहीं, बल्कि काम और भरोसे की राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर सुचित्रा नाइक की मजबूत पकड़ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। साफ-फटाई, जलापूर्ति, सड़क मरम्मत, महिला सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं जैसे बुनियादी सवालों पर उन्होंने लगातार जनता के बीच रहकर संवाद किया। डोर-टू-डोर संपर्क और बिना किसी राजनीतिक दिखावे के किए गए



अभियान ने उन्हें आम मतदाता से सीधा जोड़ दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वार्ड 37 में मतदाताओं का मूढ़ बदलाव का है। लंबे समय से उपेक्षित समस्याओं और वादों की राजनीति से ऊबे लोग अब ऐसे चेहरे की तलाश में थे, जो सत्ता में आने के बाद भी उपलब्ध रहे। सुचित्रा नाइक की स्वच्छ

छवि और जमीनी सक्रियता ने इस भरोसे को मजबूत किया है। चुनावी माहौल में जहां बड़े दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में उलझे नजर आ रहे हैं, वहीं सुचित्रा नाइक का फोकस पूरी तरह विकास और स्थानीय समाधान पर रहा। यही कारण है कि युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच उनका समर्थन तेजी से बढ़ा है।

वार्ड 37 का यह रुझान बीएमसी चुनाव में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है— कि मुंबई का मतदाता अब नाम और झंडे से ऊपर उठकर ईमानदार नेतृत्व और वास्तविक काम को चुनने के मूढ़ में है। यदि यही रफ्तार बनी रही, तो वार्ड 37 में निर्दलीय प्रत्याशी सुचित्रा नाइक की जीत एक मजबूत और निर्णायक संदेश के रूप में दर्ज हो सकती है।

वार्ड 110 : इस बार वोट नारों पर नहीं, नतीजों पर पड़ेगा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 110 अब किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं, बल्कि जनता के गुस्से और उम्मीदों का केंद्र बन चुका है। यहां चुनावी चर्चा अब 'कौन जीतेगा' से आगे बढ़कर 'कौन काम करेगा' पर आ टिक गई है। गलियों में, सोसाइटी मीटिंग्स में और चाय की दुकानों पर एक ही सवाल बार-बार उठ रहा है— क्या इस बार सिर्फ वादे होंगे या वाकई बदलाव दिखेगा? समस्याएं पुरानी हैं, लेकिन धैर्य खत्म हो चुका है।

वार्ड 110 की पहचान बन चुकी समस्याएं— अनियमित पानी, सीवर ओवरफ्लो, बारिश में जलभराव, गड्ढों से भरी सड़कें और दबाव में चलती स्वास्थ्य सेवाएं— अब मतदाताओं के लिए 'इश्यू' नहीं, बल्कि सब्र की आखिरी सीमा बन चुकी हैं।



लोग खुलकर कह रहे हैं कि हर चुनाव में वही भाषण, वही आरोप और वही बहाने सुनकर वे थक चुके हैं। जनता का मूढ़: भावनाएं नहीं, हिसाब चाहिए इस बार मतदाता भावनात्मक अपील से ज्यादा परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग रहा है। किस काम के लिए कितना फंड आया, कहां खर्च हुआ और उसका असर जमीन पर दिखा या नहीं— ये सवाल अब घर-घर में पूछे जा रहे हैं। यानी वार्ड 110 में चुनाव इमोशन से नहीं, एविडेंस से लड़ा जा

रहा है। **जेनी शर्मा : 'दिखाई देने वाली राजनीति' का दावा** बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती जेनी शर्मा को लेकर चर्चा इसलिए नहीं है कि वे किस पार्टी से हैं, बल्कि इसलिए कि वे मुद्दों से भागने के बजाय सीधे टकराती दिख रही हैं। उनका कैंपेन पारंपरिक भाषणों से अलग, घर-घर संवाद, महिलाओं से सीधी बातचीत और युवाओं के साथ आपन चर्चा पर आधारित दिख रहा है। महिलाएं,

युवा और सीनियर सिटीजन—तीनों की सोच एक लाइन में ग्राउंड फीडबैक बताता है कि: महिलाएं योजनाओं की जानकारी और सुरक्षा-स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर स्पष्ट जवाब चाहती हैं युवा रोजगार, स्किल पार्टी से हैं, बल्कि इसलिए कि वे मुद्दों से भागने के बजाय सीधे टकराती दिख रही हैं। उनका कैंपेन पारंपरिक भाषणों से अलग, घर-घर संवाद, महिलाओं से सीधी बातचीत और युवाओं के साथ आपन चर्चा पर आधारित दिख रहा है। महिलाएं,

नवनाथ बन, भाजपा मीडिया प्रमुख का तीखा हमला

डर से बौखलाए संजय राउत, हार से पहले बहानेबाज़ी शुरू

मुंबई।भाजपा मीडिया प्रमुख नवनाथ बन ने शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा कभी धमकी की राजनीति नहीं करती, बल्कि जनता के भरोसे और जनसमर्थन से काम करती है। संजय राउत द्वारा लगाए जा रहे आरोप डर और घबराहट का नतीजा हैं। यह

साफ संकेत है कि उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली है और अब हार के बहाने तैयार किए जा रहे हैं। नवनाथ बन ने कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों में जनता ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को खुला आशीर्वाद दिया है। वहीं, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों में विपक्ष की स्थिति सिंगल डिजिट तक सिमट

गई थी। यही सच्चाई संजय राउत को असहज कर रही है। उन्होंने कहा कि कुलाबा प्रकरण में आज तक संजय राउत एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। सिर्फ आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है। उल्टा, उनके भाई के वार्ड में कथित धमकियों की बातें कही जा रही हैं, जिनका भी कोई प्रमाण नहीं है।

नवनाथ बन ने आगे कहा कि मुंबईकर अब उनके साथ नहीं हैं, यह उन्हें भली-भांति समझ में आ चुका है। जनता के गुस्से और विरोध के डर से उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं की संख्या तक घटा दी है।

23 जनवरी को बालासाहेब ठाकरे की जयंती पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सजावट के नाम पर प्रतिमा

को ढंकना केवल एक मूर्ति को नहीं, बल्कि बालासाहेब ठाकरे के विचारों को ढंकने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि भाइयों की एकता की बात करने वालों ने ही बालासाहेब ठाकरे से राज ठाकरे को दूर किया। आज मनसे का रुख इसलिए साफ है क्योंकि राज ठाकरे जानते हैं कि उद्धव ठाकरे पीठ में छुरा घोंपने की राजनीति करने

हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला बोलते हुए नवनाथ बन ने कहा कि मुंबई में भ्रष्टाचार करने वालों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। संजय राउत स्वयं भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके हैं, और मुंबई की जनता यह सच्चाई अच्छी तरह जानती है।

पिछले कामकाज पर सवाल, पारदर्शिता पर नजर वार्ड में पिछले कार्यकाल को लेकर असंतोष दबा-छिपा नहीं है। काम की गुणवत्ता, ठेके और फंड उपयोग को लेकर सवाल खुलेआम उठ रहे हैं।

ऐसे में पारदर्शिता, सार्वजनिक ऑडिट और नियमित जनसंपर्क की बात करने वाला चेहरा स्वाभाविक रूप से चर्चा में है। **निष्कर्ष :** हवा नहीं, संकेत बोल रहे हैं वार्ड 110 में मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन संकेत साफ हैं— जो उम्मीदवार जवाबदेही, निरंतर संवाद और ठोस रोडमैप के साथ खड़ा है, उसे बढ़त मिलती दिख रही है। **अंतिम फँसला मतपेटी में होगा,** लेकिन जनता पहले ही साफ़ कर चुकी है— 'इस बार पहचान पोस्टर से नहीं, परफॉर्मेंस से बनेगी।'

लाडली बहनों के आशीर्वाद तथा युवाओं के साथ से हमारी जीत निश्चित : विनोद मिश्रा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

हमारे वार्ड की सबसे गंभीर समस्या यह है कि यहाँ संक्रमण शिविर बनाने का प्रस्ताव है। मैं जनता को स्पष्ट रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि इसे किसी भी स्थिति में बनने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जानूँ भोये नगर स्थित ओमकार पुनर्विकास योजना में प्रस्तावित श्मशान भूमि के आरक्षण को हटाकर वहाँ महिला आधार भवन तथा कौशल विकास केंद्र की स्थापना का ठोस निर्णय लिया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। **पानी की आपूर्ति, सीवर और जल निकासी सुधार की योजना** जल की समस्या अत्यंत गंभीर रही है। हमने नागरिकों को जल के सदुपयोग के लिए निरंतर जागरूक किया है। संजय नगर, त्रिवेणी नगर (ज्योति होटल के पास) तथा रमेश होटल परिसर में छह इंच की नई जलापूर्ति पाइपलाइन का कार्य पूर्ण किया गया है। वार्ड में प्रमुख जल रिसाव की समस्याओं का समाधान किया गया है।

झोपड़पट्टी और चॉल क्षेत्रों में पुरानी और छोटी पाइपलाइनों को हटाकर बड़े आकार की नई पाइपलाइन डाली गई है। अग्निशमन जल बिंदुओं को भी उन्नत किया गया है। इन सभी प्रयासों से वार्ड में जल से जुड़ी अधिकांश समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। **सड़क, गड्ढे और फुटपाथ सुधार** मैं अपने नागरवासियों के साथ निरंतर कार्य करता हूँ। वार्ड 43 की सभी प्रमुख मुख्य सड़कों का शत-प्रतिशत निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया गया है। आंतरिक सड़कों तथा पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए फुटपाथों का कार्य भी पूर्ण किया गया है। फुटपाथ रेलिंग का कार्य जारी है, जिससे अवैध फेरीवालों और अनधिकृत वाहन पार्किंग पर नियंत्रण रखा जा सके।

कचरा प्रबंधन और स्वच्छता वार्ड में पहले सात कचरा पेटियाँ थीं, जिनसे अत्यधिक गंदगी होती थी। इनमें से पाँच कचरा पेटियाँ हटाई जा चुकी हैं और शेष दो को भी हटाया जाएगा। कचरा पेटियों के स्थान पर स्थायी कचरा संग्रह व्यवस्था विकसित की गई है। हमारा लक्ष्य वार्ड 43 को मुंबई का सबसे स्वच्छ और आदर्श



वार्ड बनाना है। **बरसात में जलभराव की समस्या** वार्ड में शत-प्रतिशत गटर और जल निकासी का कार्य पूर्ण किया गया है। नालों की गाद निकासी और वर्षा ऋतु से पूर्व की गई योजनाबद्ध तैयारियों के कारण जलभराव की समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाएँ वार्ड के महानगरपालिका स्कूलों में खेल मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल मैदान, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ और जिनका नियमित रखरखाव किया जाएगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निगरानी कैमरों की व्यवस्था की गई

है। वीर सावरकर मैदान में खेल से संबंधित सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान (शांताराम तालाब) तथा बाबा बालक दास उद्यान, शिवाजी नगर को मुंबई के श्रेष्ठ उद्यानों के रूप में जगाना। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निगरानी कैमरों की व्यवस्था की गई

और सुदृढ़ किया जाएगा। **युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण** वार्ड में कौशल विकास केंद्र की स्थापना, रोजगार मेलों का आदेश मेरे लिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, लाडली बहन योजना से संबंधित दस्तावेज़ी और अन्य समस्याओं का समाधान करना तथा युवाओं के लिए मेरे जनसंपर्क कार्यालय में विशेष सुविधाओं की स्वतंत्र व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता है।

नगरपालिका निधि का पारदर्शी उपयोग

सभी कार्य आदेश मेरी वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। यह सर्वविदित है कि विपक्ष द्वारा किए गए कई घोटालों को हमने उजागर कर निरस्त कराया है। मैं हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहा हूँ और मुंबईकरों की मेहनत की कमाई का ईमानदार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं प्रतिदिन अपने जनसंपर्क कार्यालय में नागरिकों से मिलता हूँ और मोबाइल, ईमेल, संदेश सेवा, हेल्पलाइन तथा सामाजिक माध्यमों के जरिए निरंतर संपर्क में रहता हूँ। कोरोना काल से चौबीसों घंटे सक्रिय

हेल्पलाइन आगे भी नागरिकों की सेवा में जारी रहेगी।

जनता ने यदि मुझे अवसर दिया है तो जनता जनार्दन का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अपने कार्यकाल में मैंने उन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है जो पिछले पचास वर्षों से अधूरे थे, जैसे वार्ड की सभी सड़कों का सीमेंट कंक्रीटीकरण, संपूर्ण सीवर लाइन का निर्माण, डाकघर और डायलिसिस केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाओं की शुरुआत। अस्पताल के लिए भूमि आर्क्षित कराना, राशन कार्यालय की मंजूरी, पी-पूर्व कार्यालय के लिए स्थायी स्थान, अत्याधुनिक स्कूल, उद्यान और मैदानों का विकास मेरे कार्यों का प्रमाण है। कोरोना काल में, जब अन्य लोग क्षेत्र छोड़ चुके थे, तब भी हमने मुंबईकरों की सेवा की। 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के संकल्प के साथ मेरा स्पष्ट लक्ष्य वार्ड 43 को कुरार और पठानवाड़ी के सभी निवासियों के हित में एक आदर्श वार्ड बनाना है। लाडली बहनों के आशीर्वाद और युवाओं के साथ से हमारी जीत निश्चित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं वार्ड 43 के लिए सबसे योग्य और सक्षम उम्मीदवार हूँ।